BILL INTRODUCED

THE FORFEITURE (REPEAL) BILL, 2000

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI I.D. SWAMI): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to repeal the Forfeiture Act, 1859.

The question was put and the motion was adopted.

SHRI I.D. SWAMI: Sir, I introduce the Bill.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURESH PACHOURI): The House is adjourned for lunch, for half-an-hour.

The House then adjourned for lunch at fifteen minutes past two of the clock.

The House reassembled after lunch at forty-nine minutes past two of the clock. THE VICE-CHAIRMAN (SHRI T.N. CHATURVEDI) in the Chair

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI T.N. CHATURVEDI): Hon. Members; there are two Constitution Amendment Bills, i.e. the Constitution (Eighty-Sixth) Amendment Bill, 1999 and the Constitution (Eighty-Eighth) Amendment Bill, 1999 which are listed in the Agenda Paper for consideration and passing. If the House agrees, we can first take up the Constitution (Eighty-Eighth) Amendment Bill, 1999. These two Bills are to be passed by a special majority as required under article 368 of the Constitution. To enable the Members to be present in the House at the time of Division at various stages, the first Division on the Bill will be at 4 p.m. I hope this meets with the approval of the House. So we start with the Constitution (Eighty-Eighth) Amendment Bill, 1999.

THE CONSTITUTION (EIGHTY-EIGHTH AMENDMENT) BILL, 1999

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS (SHRIMATI VASUNDHARA RAJE): Sir, I move:

"That the Bill further to amend the Constitution of India be taken into consideration."

Sir, the Constitution (Eighty-Eighth Amendment) Bill, 1999, was introduced in this House on 23rd December, 1999. Under this Bill, it is proposed to incorporate a proviso under article 335 of the Constitution to enable the State to provide relaxations of qualifying marks and standards of evaluation in matters of reservation in promotion to Scheduled Castes and Scheduled Tribes. I may mention, Sir, that these relaxations to Scheduled Castes and Scheduled Tribes had been in vogue until July 22, 1997 when they were withdrawn by an order of the Department of Personnel and Training issued in pursuance of the Supreme Court Judgement in the case of S. Vinod Kumar vs. Union of India.

The Bill seeks to enable the State to overcome the adverse effect of the aforesaid Office Memorandum dated July 22, 1997 and to restore the position as existed prior to that date. The aforesaid amendment to the Constitution would enable the Government to enlarge the scope of promotion of Scheduled Castes and Scheduled Tribes against the posts reserved for them by according necessary relaxations. I may also mention that the National Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes were also consulted in the matter and they have welcomed the proposed amendment.

The Department-related Parliamentary Standing Committee on Home Affairs in its Sixty-Sixth Report on the Constitution (Eighty-Eighth Amendment) Bill, 1999, presented to this hon. House and laid before the Lok Saha simultaneously on July 28, 2000 has expressed agreement with the provisions of the Bill and has also recommended the passing of the Bill in its present form. As the Committee has made this recommendation after an in-depth examination of the Bill, I would request the hon. Members to pass the Bill unanimously.

With these words, I commend the Bill for the consideration of the House.

The question was proposed.

डॉ. फागुनी राम (बिहार) : उपसभाध्यक्ष महोदय, यह कांस्टीट्यूशन का जो संशोधन है यह बड़ा प्रशंसनीय है क्योंकि एससी और एसटी के प्रमोशन्स को रोका गया था उससे एससी,एसटी के लोगों का मनोबल गिरा था। उनका जो उज्ज्वल भविष्य था, प्रमोशन लेकर आगे जाते थे, वह रुक गया था। सन् 1972 से जब से यह आरक्षण लागू हुआ है तब से ही आरक्षण मे प्रमोशन का प्रावधान था और तभी से लोग इससे बेनिफिटिड हो रहे थे। किसी कारणवश यह बीच में रुक गया था तब हम लोगों को यह लगा था कि अच्छी-अच्छी पोस्टों पर, जहां लोग बहाली में बैठते हैं और निर्णय लेने में बैठते हैं, वहां शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग नहीं पहुंच सकेंगे, इसीलिए यह जरूरी था। सरकार का यह कदम बहुत प्रशंसनीय है। हम सभी शैड्यूल्ड

कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग सरकार के इस कदम के आभारी हैं कि इसमें सुधार करके पुन: बहाल किया। इससे शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों की प्रमोशन का प्रावधान हो सकेगा। यह एक प्रशंसनीय कदम है और हम सरकार की प्रशंसा करते हैं, आदर करते हैं और इस बिल के लिए आभार व्यक्त करते हैं। यह बात सही है कि रिजर्वेशन और प्रमोशन में शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को जितना हक मिलना चाहिए था, वह नहीं मिलता है। इस बिल के पास हो जाने के तुरन्त बाद यह लागू हो जाना चाहिए ताकि उनको प्रमोशन मिलने लगे। जिन पर रोक लगी थी, जिनकी प्रमोशन होनी चाहिए थी उस बारे में भी विचार किया जाना चाहिए और रुके हुए कामों को द्रुत गति से आगे ले जाना चाहिए। नियुक्तियां और प्रमोशन दोनों में आरक्षण होना इनके उत्थान के लिए जरूरी हैं क्योंकि सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक दृष्टि से जहां तक इनको जाना चाहिए था, अभी वहां तक ये लोग नहीं पहुंचे हैं, इनको वहां तक पहुंचाने के लिए यह प्रावधान जरूरी है।

हर क्षेत्रीय डिपार्टमेंट में पहले नौकरी के लिए अधिक लोग नहीं मिलते थे। प्रमोशन रिजर्वेशन का प्रावधान है, एक मौका है। उन्हें मौका मिला इसलिए आज हर एक महकमे की पोस्टों पर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग विद्यमान हैं। यह बात भी देखने में आई है कि उनके लिए आरक्षण का जितना प्रावधान है या जितनी सीटें आरक्षित हैं उतने कैंडीडेट नहीं मिल पाते। कैंडीडेट तो रहते हैं लेकिन जितनी योग्यता निर्धारित की जाती है वे उसके अंतर्गत नहीं आ पाते। किसी विशेष पद के लिए जो अर्हता निर्धारित की जाती है और जिसकी वजह से कैंडीडेट नही मिल पाते उसे दूर करने के लिए परीक्षा से पूर्व एक ट्रेनिंग उन कैंडीडेट्स को देनी चाहिए, उन्हें पर्याप्त प्रशिक्षण देना चाहिए ताकि वे लोग जहां कम्पीटीशन हो वहां कम्पीट करके भी आ सकें और शेड्यूल्ड कास्ट तथा शेड्यूल्ड ट्राइब्स की पोस्टों को भरा जा सके।

शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को नौकरी की जरूरत है इसलिए उनकी अनएम्प्लोएमेंट दूर करने के लिए, उन्हें मेन धारा में आने के लिए, हर रिजर्व पोस्ट पर, हर प्रमोटिड पोस्ट पर उनके आदमी लाने के बारे मे भी हमें सोचना चाहिए और इसे त्वरित गति से लागू करना चाहिए। जो पोस्टें खाली रह गई हैं या जो आगे भरी जाएंगी, उसमें बैकलॉग नही रहे, इसका प्रबंध करना चाहिए क्योंकि बैकलॉग होने से यह होता है कि धीरे-धीरे वह पोस्ट समाप्त हो जाती है। खैर अब वह बात नहीं रही उसे समाप्त किया जा रहा है, यह ठीक ही है। जितनी पोस्टें रिजर्व होती हैं यह प्रयास करना चाहिए कि साइमल्टेनियसली उतने लोगों की बहाली हो सके। जब तक यह नही होगा तब तक इसका समाधान नही हो सकेगा। उन्हें प्रिरिक्रूटमेंट पर्याप्त प्रशिक्षण देना चाहिए ताकि वे कंपीटीशन के लिए अपनी योग्यता हासिल कर सके। इससे उनका मनोबल बढ़ेगा,उनकी पोस्टों का फुलफिलमेंट हो जाएगा और वे लोग आगे आएंगे हालांकि वे लोग आज साधारण पोस्ट पर तो हैं ही । प्रमोशन रुक गया था, एक स्टेट से दूसरे स्टेट मे जाना भी रुक गया था। उन्हें प्रमोशन के इवेन्यूज कम्पीटीशन मे कम मिल पाते थे। इसमे जो प्रावधान हो रहा है उसकी वजह से उन्हें मौका मिलेगा और वे प्रमोटड पोस्ट पर भी आगे जा सकेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि यह साइमल्टेनियसली भरना चाहिए और इसे भरने के लिए जो भी प्रयास हों, ट्रेनिंग का, उनकी योग्यता बढ़ाने का वह भी करना चाहिए ताकि इन लोगों को मौका मिल सके और वे अपने अधिकार, अपने आरक्षण के लाभ से वंचित न रह सकें। इन्ही शब्दो के साथ मुझे आशा है कि इस बिल से शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को लाभ मिलेगा, उनका मनोबल बढ़ेगा और वे ऊंची-ऊंची पोस्टो पर जा सकेंगे। मैं तहेदिल से इसका समर्थन करता हूं।

3.00 P.M.

श्री राम नाथ कोविन्द (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष जी, मैं कांस्टीट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, 1988 के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। महोदय, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था दिनांक 1 अक्तूबर, 1996 का "विनोद कुमार वर्सज यूनियन ऑफ इण्डिया" जिसके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने यह होल्ड किया कि आर्टिकल 335 संविधान में जो कमांड दी गई है उसके अनुसार आर्टिकल 16 (4) के तहत जो रिलेक्सेशन का प्रावधान है शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए वह उचित नहीं है। महोदय, इस जजमेंट से पूर्व इस प्रकार के रिलेक्सेशन की व्यवस्था थी और इस बिल के माध्यम से हम कोई नया प्रावधान अनुसूचित जाति-जनजाति के कर्मचारियों के हितों के लिए नहीं दे रहे हैं बल्कि जो पहले दिया गया था जो बीच में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के तहत वापिस ले लिया गया उसे ही रिस्टोर करने जा रहे हैं। महोदय, वर्ष 1997 में जिस समय तथाकथित सामाजिक न्याय की सरकार थी उस वर्ष पांच ऑफिस मेमोरेंडम जारी हुए थे। जो आरक्षण की नीति थी उसको उन सभी मेमोरंडाज ने दुष्प्रभावित किया। इससे जो अनुसूचित जाति और जनजाति के कर्मचारी थे, वह बहुत उद्वेलित हुए। उन्होंने बराबर धरना और प्रदर्शन किए। यहां तक कि हम सभी सांसदों से मिलकर उन्होंने अपनी गुहार लगाई। इसके पश्चात हम सभी सांसद बहुत बड़ी संख्या में तत्कालीन प्रधानमंत्री देवेगौड़ा जी से मिलते रहे, गुजराल साहब से मिलते रहे। लेकिन जो कुछ होना चाहिए था वह नहीं हुआ। हमने अपने तर्क दिए, दलीलें दीं लेकिन उनके बावजूद यह बात सामने नहीं आई। 1998 में जब श्री अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने तो उनके समक्ष भी बहुत सारे सांसद, जिन में मैं भी था, प्रधानमंत्री जी से मिले और अनुसूचित जाति और जन-जाति पर आरक्षण का जो दुष्प्रभाव हुआ था, उसके परिणामों से उनको अवगत कराया। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि कहीं न कहीं ये जो आफिस मेमोरंडाज जारी हुए हैं, इनमें कुछ गलती रह गई है और इसके कारण इन सभी कर्मचारियों को एक अच्छा संदेश नहीं जा रहा है, उनका अहित हो रहा है। इसलिए उस दौरान फिर उन्होंने आश्वासन भी दिया। इसके पश्चात जब नई सरकार बनी, वर्ष 1999 में, पिछले वर्ष, तो मुझे याद है कि 5, 6, 7 दिसम्बर, 1999 को अपने प्रकार का एक आल पार्टी शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्स कन्वेंशन पार्लियामेंट हाउस एनेक्सी में हुआ। उस कन्वेंशन का प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया और उद्घाटन करते समय उन्होंने कुछ ओएमएस का उल्लेख भी किया और यह भी कहा कि हम शीघ्र से शीघ्र इन्हें विदड्रा करने वाले हैं। दुर्भाग्यवश, उसमें जो हमारे कांग्रेस के मित्र थे उन्होंने उसका वाक-आउट किया, यद्यपि बाद में वे आ गए थे। लेकिन, महोदय, मैं यहां पर यह कहना चाहता हूं कि उस समय भी प्रधानमंत्री जी ने जो आश्वासन दिया था, उस आश्वासन के तहत उन्होंने 22 दिसम्बर, 1999 को लोकसभा में एक स्टेटमेंट दिया। मैं उसको कोट करना चाहूंगा जो कि इन आफिस मेमोरंडा के बारे में है :

"In respect of one of the Office Memoranda, the Cabinet in its meeting held on 21st December, 1999 has approved the proposal to bring about a Constitutional (Amendment) Bill to incorporate a proviso to article 335 of the Constitution with a view to enable the State to restore the relaxations of qualifying marks and standards of evaluation in the matter of reservation and promotion for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. It may be recalled that

these relaxations had been withdrawn as per the instructions issued by the Department of Personnel and Training on 22nd July, 1997 in pursuance of the Supreme Court judgment dated 1.10.1996 in the case of S. Vinod Kumar vs. Union of India. I may also mention that the National Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes was also consulted on this aspect and that the Commission has expressed its appreciation of the proposed amendment. The proposed Constitutional (Amendment) Bill will be introduced in the Parliament as early as possible."

महोदय, इसके तुरन्त पश्चात् यह 22 दिसम्बर को दिया गया और 23 दिसम्बर, 1999 को, जैसा अभी मंत्री महोदया ने अपने भाषण में उल्लेख भी किया, इस बिल को राज्य सभा में पेश किया गया। किन्हीं कारणों से महोदय, इस बिल को स्टेडिंग कमेटी, होम मिनिस्ट्री को रेफर कर दिया गया। इस बीच में उसकी रिपोर्ट भी आ गई है और अब यह बिल इस सदन के सामने कंसीडरेशन और पैसेज के लिए हमारे सामने आया है।

मैं यहां पर एक बात का उल्लेख करना चाहूंगा। जो पांच आफिस मेमोरेंडम जारी हुए थे, उनके बारे में प्रधानमंत्री जी ने जो आश्वासन दिया था। उनमें से एक आफिस मेमोरेंडम को विदड्रा करने से संबंधित कांस्टीट्यूशनल अमेंडमेंट बिल संसद के माध्यम से आलरेडी पास हो चुका है। यह जो आज आपके सामने बिल है, इसके माध्यम से दूसरा आफिस मेमोरेंडम विदड्रा हो सकेगा। इसके पश्चात् प्रधानमंत्री जी ने एक स्टेटमेंट लोक सभा में दिया था, उसमें उन्होंने एक बात का और जिक्र किया था, जो महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा था - The proposal to bring about another Constitutional amendment, which would make it possible to clear the backlog of jobs through special recruitments in respect of Scheduled Castes and Scheduled Tribes, is also at the final stage of consideration.

महोदय, यह बिल बहुत पहले पास हो चुका है और उसके संबंध में गज़ट नोटिफिकेशन भी हो चुका है। तीसरी बात उन्होंने कही थी - The Constitution Bench of the Supreme Court in a recent judgment dated 16.9.99 has reiterated its earlier judgments regarding the principle of fixation of seniority on promotion of Scheduled Castes and Scheduled Tribes employees. The legal and Constitutional aspect of this judgment is under examination with a view to bring about a Constitutional amendment to restore the seniority principle that was prevalant prior to these judgments. Mr. Speaker, Sir, I would like to assure the House that this Government is committed to protect the interests of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes employees and will take all possible steps for their upliftment. महोदय, मैं इस अवसर पर इस बात का उल्लेख करना चाहूंगा कि जिस आफिस मेमोरेंडम के बारे में उन्होंने उल्लेख किया है रिगार्डिंग रेस्टोरेशन आफ सीनियर्टी प्रिंसिपल, उसी से जुड़ा हुआ एक रोस्टर सिस्टम का आफिस मेमोरेंडम है। मुझे लगता है कि यदि हमारी सरकार शीघ्रातिशीघ्र इस बारे में संविधान संशोधन बिल लाएगी

तो दो और आफिस मेमोरेंडम विदड्रा हो सकेंगे। उनसे आरक्षण नीति दुष्प्रभावित हो रही है। मैं चाहूंगा मंत्री महोदया से कि आज वे इस संबंध में अपने वक्तव्य में जरूर इस बात का आश्वासन दें कि इस संबंध में रिगार्डिंग रेस्टोरेशन आफ सीनियर्टी प्रिंसिपल के बारे में कब तक बिल पेश करने वाली हैं।

अंत में उपसभाध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जब कांस्टीट्यूंट अस्सेंबली में इस पर डिबेट चल रही थी, उस समय भी यह चर्चा का विषय था कि आफ्टर आल हम आरक्षण का प्रावधान रख रहे हैं, अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए उनको बराबरी का दर्जा देने के वास्ते उनके मन में क्या था। उसका मै उल्लेख करना चाहूंगा और मैं कोट करना चाहूंगा। इस मुद्दे पर आर्टिकल 335 पर जो चर्चा हो रही थी यद्यपि कांस्टीट्युंट अस्सेंबली में जब चर्चा हुई थी उस समय यह आर्टिकल 296 था लेकिन उसके बदले में यह हमारा वर्तमान आर्टिकल 335 बना। 4 अक्तूबर, 1949 को श्री एच.वी.कामथ ने डिबेट में भाग लेते हुए कहा था--I only wish to express the hope that before ten years have expired from the commencement of the Constitution in this country of ours which has had an ancient history, this country of ours which is ancient but ever young, there will be not merely no backward classes, socially and educationally backward classes, left but that all the classes will come up to a decent normal human level and also that we shall do away with this stigma of any caste being scheduled. This was a creation of the British regime which happily has passed away. We have taken many strides forward in removing or doing away with the numerous evils that were associated with the British regime. This is one of the few that still remain. I hope, Sir, that this stigma too will disappear from our body politic and we shall all stand before the world as one single Indian human community.

महोदय, एच.वी. कामथ साहब जो हमारे संविधान निर्माताओं में एक थे और अन्य लोगों के मन में जो नीयत और लक्ष्य था वह यह था कि पहले के मात्र दस वर्ष जो उन्होंने तय किए थे - यह सबको विश्वास था कि शायद ये दस वर्ष इस वर्ग को बराबरी के दर्जे पर लाने के लिए पर्याप्त होंगे। बराबरी, सामाजिक और आर्थिक क्योकि राजनीतिक दृष्टि से तो बराबरी ला दी गयी है, बहुत कुछ आरक्षण दे कर संसद में लोक सभा में, विधान सभाओं में और अब तो पंचायतों में भी। लेकिन जो सामाजिक और आर्थिक बराबरी की बात सोची गयी थी उसके लिए आरक्षण नीति के माध्यम से अथवा अन्य स्कीमे जो इनके उत्थान के लिए चलायी गयी थीं, योजनाएं बनायी गयी थीं उनके माध्यम से सोचा गया था कि दस वर्ष पर्याप्त होंगे। लेकिन महोदय 10 वर्ष बीत गए, 20 वर्ष बीत गए, 30 वर्ष बीत गए, 40 वर्ष बीत गए और अब 50 वर्ष बीत गए। पांच बार हमने दस-दस साल के लिए यह कार्यावधि, यह समयावधि बढायी यद्यपि सर्विसेज में किसी भी प्रकार की कोई लिमिटेशन नहीं है। राजनीतिक दृष्टि से हम संविधान की जो मर्यादा है वह दस-दस साल बढ़ाते रहे। लेकिन वह लक्ष्य जो था वह लक्ष्य हम अभी तक पा नहीं पाए हैं। महोदय, मैं इस संबंध में इतना ही कहूंगा कि आज इस देश के सामने एक बहुत बडी चुनौती है। देश की एकता और अखंडता की बात हम करते हैं। वह पैरामाउंट है। लेकिन यह जो पिछड़ा वर्ग है, दलित वर्ग है, आदिवासी वर्ग है और दूसरे गरीब तबके हैं इन लोगो मे जो आर्थिक बराबरी आनी चाहिए वह आज

भी नहीं आ पा रही है जो कि अपेक्षा की गयी थी।

महोदय इस संबंध में मैं कुछ दो-तीन कारणों की ओर ध्यान दिना चाहूंगा इस सदन के सामने। इसके लिए जो हमारी ब्यूरोक्रेसी थी वह - जो राजनीतिक दलों की सहमति बनी, संसद की सहमति बनी और जो वह दस वर्ष की हमारे संविधान निर्माताओं की सहमति बनी - उस सहमति को एक करेक्ट पर्सपेक्टिव में नहीं देख पायी। यदि देखा होता तो मुझे लगता है कि अगर 10 वर्ष में यह पूरा नहीं हो सकता था तो 20 वर्ष में पूरा हो जाता, 20 वर्ष में पूरा नहीं हो सकता था तो 30 वर्ष में पूरा हो जाता। यद्यपि मैं किसी प्रकार का एसपर्शन कास्ट नहीं करता हूं। लेकिन फिर भी जिस नीयत के साथ संविधान निर्माताओं ने इस बात को, लक्ष्य को रखा था वह लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। महोदय, इस संबंध में चूंकि 50 वर्ष बीत गए हैं आज आम जनता में - इस वर्ग को छोड़कर - जो देश की आम जनता है उनके मन में भी कहीं न कहीं एक भ्रम आ जाता है कि 50 वर्ष यह कब तक आरक्षण चलता रहेगा। क्या यह कोई परमानेंट आरक्षण चलेगा? यदि परमानेंट चलेगा तो फिर इसके लिए कौन जिम्मेदार है? जो दूसरे लोग हैं वे पीछे होते जाएंगे। जो आगे बढ़ने वाले हैं उनमें से कुछ वर्ग आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन जो एक सकारात्मक मानसिकता थी आम जनता की उसमें परिवर्तन हुआ है। महोदय, मैं यह जरूर चाहूंगा कि एक समाधान की दृष्टि से यदि राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए हमारी एक राष्ट्रीय सहमति बनती है उसी प्रकार से मैं चाहूंगा कि इन वर्गों के कल्याण के लिए इस वर्ग को सामाजिक और आर्थिक बराबरी में लाने के लिए एक हमारी राष्ट्रीय सहमति बने। राजनीतिक सहमति तो बन जाती है। उसके कई दूसरे मीनिंग भी होते हैं, कई कारण भी होते हैं। लेकिन राष्ट्रीय सहमति की मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि जब तक आम जनमानस की राष्ट्रीय सहमति में भागीदारी नहीं होगी तब तक यह जो कल्याणकारी और आरक्षण की नीतियां हैं सही रूप में उनका लक्ष्य और परिपालन पूरा नहीं हो सकेगा।

महोदय, मैं एक दूसरी बात और कहना चाहता हूं कि संविधान में भी अनटचेबिलिटी, छुआछूत को हमने एक काग्नीजिबुल आफेंस माना है। यह भी 10 वर्ष - 20, 30, 40, 50 वर्षों की आरक्षण नीति से संबंधित है। जो अधिकारी अथवा कर्मचारी जिनको एक जिम्मेदारी जाती है टु सम एक्सटेंट, मुझे लगता है कि यदि कहीं उसमें भी कोई पीनल क्लाज की व्यवस्था करें या जिस तरीके से अनटचेबिलिटी को हमने काग्नीजिबुल आफेंस माना है उसी तरीके से यदि जिम्मेदार कर्मचारी या अधिकारी जो इस संबंध में है उनकी जो इस बारे में कमी रह जाती है वे असफल रह जाते हैं। इस काउंट पर भी यदि हम कोई ऑफेंस ट्रीट करें तो मुझे लगता है कि शायद जो हमारी कार्य प्रणाली है इसमें कुछ बदोत्तरी होगी।

उपसभाध्यक्ष महोदय, तीसरी चीज़ मैं कहना चाहूंगा कि आज तक जितने भी आरक्षण के कानून हैं, आरक्षण की नीतियां हैं, आरक्षण के प्रावधान हैं, they are all governed by office memoranda. किसी भी प्रकार का उनको लागू करने का कानून नहीं है। There is no resolution as such. यही कारण है कि ब्यूरोक्रेसी का जो उनकी अपनी समझ में आता है, कहीं न कहीं लूपहोल निकाल करके और किसी न किसी तरीके से कि इसमें यह कमी है, इस तरीके से, इस प्रकार का ऑफिस मेमोरेंडा जारी किया जाए या कुछ संशोधन किए जाएं, वह करती रहती है। इससे एक गलत मैसेज भी जाता है। इसलिए मैं यही चाहूंगा और इस सदन से भी दरख्वास्त करूंगा कि मैं जो निवेदन कर रहा हूं उसमें मुझे लगता है कि आप सब का सहयोग मिलेगा। मैं मंत्री जी से भी निवेदन करूंगा कि आगे इस संबंध में तुरंत कार्यवाही करें और अभी

तक जो ऑफिस मेमोरेंडा के थ्रू रिज़र्वेशन पालिसी गवर्न होती है उस पर रोक लगे। संविधान मे एक कंप्रीहैंसिव रिज़र्वेशन एक्ट लाया जाए। एक्ट बने और उस एक्ट को नाइन्थ शैड्यूल में रख दिया जाए तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं छुटपुट जो कोर्ट की घटनाएं हो जाती हैं और किसी प्रकार की रोक लग जाती है तो उनसे भी हम सब को लाभ मिलेगा।

अंत में मैं चाहूंगा कि जो प्रधान मंत्री जी ने आश्वासन दिया था regarding restoration of seniority principle वह बिल शीघ्र से शीघ्र पेश किया जाए। महोदय, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री रामदेव भंडारी (बिहार) : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है। 22.7.1997 तक शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब के लोगों को प्रोमोशन में भी आरक्षण का प्रावधान था लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के अनुसार इसे समाप्त कर दिया गया और आज सन् 2000 के अगस्त महीने में पुन: एक विधेयक को हम पारित करने जा रहे हैं जिससे फिर से प्रोमोशन में जो आरक्षण का प्रावधान था वह लागू होगा। महोदय, यह तीन वर्ष का समय, इस प्रावधान को वापस करने के लिए काफी लंबा समय लगा, ऐसा मैं महसूस करता हूं, क्योंकि जब प्रोमोशन में आरक्षण का प्रावधान समाप्त कर दिया गया होगा तो इन तीन वर्षों में सैंकड़ों की संख्या में प्रोमोशन पाने के हकदार शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब के लोगों का प्रोमोशन रुक गया होगा। मैं माननीय मंत्री जी से यह भी जानना चाहूंगा और सुझाव भी देना चाहूंगा कि इसको रेट्रोस्पेक्टिव इफैक्ट से लागू करना चाहिए क्योंकि 1997 के बाद से प्रोमोशन रुक गए थे। महोदय, हमारे संविधान निर्माताओं ने जिस समय शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब के लिए आरक्षण की व्यवस्था की तब उन्होंने महसूस किया कि जो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से दलित हैं, पिछड़े हैं, समाज में बहुत पिछड़े हैं, उन्हें बराबरी पर लाने के लिए, उनके लिए विशेष प्रावधान करने की आवश्यकता है और इसी के तहत उन्होंने आरक्षण का प्रावधान किया। मगर आरक्षण का प्रावधान करने के बाद भी जिस अनुपात में उनको आरक्षण मिलना चाहिए था, उस अनुपात में अभी तक उनको आरक्षण नहीं मिला है। मैं पार्लियामेंट की शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब कमेटी का मैंबर था। जहां-जहां भी इंस्पैक्शन में वह पार्लियामेंटरी कमेटी गई हर जगह उसने देखा कि भारी संख्या में बैकलॉग .....।

एक जवाब आता था कि सूटेबल केंडीडेट्स नहीं मिलते हैं, इसलिए बैकलॉग है। महोदय, यह कितनी बड़ी विडंबना है कि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब में उन को सूटेबल केंडीडेट्स नहीं मिलते। महोदय, कोई ऐसा विभाग नहीं, जहां कि बैकलॉग नहीं हो और बैकलॉग भरने के लिए जब स्पेशल रिक्रूटमेंट की बात होती थी तो वह भी ठीक ढंग से लागू नहीं किया जाता था। महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि हमारे समाज की अभी भी यह मानसिकता नहीं बनी है कि दलित और पिछड़ों को न्याय मिले। ऐसी मानसिकता बनाने की जरूरत है। मैं एक बार फिर आप के माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट में अभी भी जो शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब मायनॉरिटी और बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, उन का हाईकोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में रिप्रजेंटेशन नहीं के बराबर है और उस का एक कारण यह भी है कि संविधान निर्माताओं ने जो यह इतना महत्वपूर्ण फैसला लिया था, उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया। महोदय, दलित वर्ग के लोगों और पिछड़ों का रिप्रजेंटेशन बहुत जरूरी है। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि जिस तरीके से आई.ए.एस./आई.पी.एस. की परीक्षाओं में रिजर्वेशन है, उसी तरह से सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट्स में भी रिजर्वेशन का प्रावधान होना चाहिए क्योंकि सोशल बैकग्राउंड का असर

निश्चित रूप से पड़ता है। महोदय, मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूं, न ही मैं कोर्ट की आलोचना करने के लिए खड़ा हुआ हूं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि सोशल बैकग्राउंड का असर पड़ता है और जब सामाजिक न्याय और शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब और ओ.बी.सी. की बात होती है तो उस मामले में कहीं-न-कहीं अड़ंगा खड़ा किया जाता है।

महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है और मैं पुन: एक बार कहना चाहूंगा कि यह जो बीच का पीरिएड है, 27.7.97 के बाद का पीरिएड है, इस में जिन लोगों का प्रमोशन नहीं हुआ है, उन को रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से प्रमोशन दिया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI KHAGEN DAS (Tripura) : Mr. Vice-Chairman, Sir, I rise to support the Bill. But while supporting the Bill, I want to make some points on the woes and sufferings of the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other downtrodden people, with a view to striking mildly at the hearts of the people who are at the helm of affairs to see whether they have any real heart to do something for the poorest of the poor. After gaining independence, we framed the Constitution to create a new society based on the principles of equality, justice and fraternity. The Constitution provides certain special protection and help for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. But, unfortunately, even after the commencement of the Constitution, the same colonial law which had taken away from the people their right to life continued as before. A most ironical situation has developed in which there is a basic anomaly between the law and the Constitution. In many parts of the country, there remains nothing for the SC/STs, especially the tribal people, to call as their own. Not only this; under the patronage of this law, their everything is being snatched away.

The most regrettable aspect is, the sacred right of the people, the right to lead a respectable life, is being violated. May I know what has been done to recognise their right to the continuous use of natural resources such as water, forests and land - who earn their livelihood from there-and, accordingly, to uphold the principle of land to the tiller? A study of the National Commission for SC/ST...*(Interruptions)*...

उपसभाध्यक्ष (श्री टी.एन. चतुर्वेदी) : आपका तीन मिनट का टाइम है, कृपया तीन मिनट में वाइंड-अप कीजिए।

SHRI KHAGEN DAS: Okay, Sir. I will conclude in two or three minutes. It is an important issue, Sir. A study of the National Commission for SC/ST shows that the number of cultivators who own land has decreased from 37.76% in 1961 to 25.44% in 1991, so far as SCs are concerned. So far as STs are concerned, the number has decreased from 68.18% in 1961 to 54.5% in 1991. They are forced to sell their lands, or,

their lands are being taken away forcibly. Restoration of illegally transferred tribal lands is negligible and the right to continuous use of the forests has been denied. So, pauperisation is taking place at a faster pace. Even after 52 years of Independence, a large number of tribal people depend on shifting cultivation. Then, a special provision was made for reservation in jobs.

Fifteen per cent reservation was made for SCs and 7.5% reservation was made for STs. But till now, we have not reached the expected level in both the Central Government Departments and the public sector undertakings. There is no political will to implement it. I would like to know from the hon. Minister as to whether, during the last 52 years, anybody has been punished for non-implementation of this provision. The National Commission for SCs and STs recommended some special penal provision for non-implementation of this provision. I request the Government to make sure that this programme does not remain simply on papers. Then, some new issues have emerged because of the new economic policies - less jobs. Due to privatisation of public sector undertakings, the opportunities for jobs are on the decline in both the Government Departments and the public sector undertakings. Our education is in a crisis. You are developing a parallel education system to cater to the needs of the elite section, depriving the SCs, the STs and the poorer sections. Public health facilities are on the decline; the public distribution system is being dismantled; various changes in the agrarian sector have taken place; all these issues are required to be addressed. I propose that a monitoring cell, with statutory powers, is required to be set up. Lastly and finally, I urge upon the Government that the responsibility-in case there is a violation of the Constitution-should be fixed and the persons concerned should be brought to book.

श्री रमा शंकर कौशिक : श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि हमारे यहां से हमारी पार्टी के कई संसद सदस्य, राज्य सभा के सदस्य - श्री जनेश्वर मिश्र, श्री रामगोपाल यादव, मोहम्मद आज़म खान साहब आज एटा जा रहे थे, उनको बीच में रोक लिया गया है। वहां स्थिति बड़ी खराब है, पुलिस की गोली भी चल सकती है, वहां बड़ी भीड़ इकट्ठा हो रखी है, लोग एटा में उनका इंतज़ार कर रहे हैं और ऐसी स्थिति हो गई है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एटा को एकदम छावनी बना डाला है, सब लोगों को रोक रखा है। श्रीमन्, मैं जानना चाहता हूं और चाहता हूं कि आप जरा सरकार से कहिए कि वह इस बारे में बताए तो सही कि श्री मुलायम सिंह यादव, श्री जनेश्वर मिश्र, श्री रामगोपाल यादव, मोहम्मद आज़म खान तथा और भी हमारे बहुत से संसद सदस्य कहां हैं, किस हालत में हैं?

उपसभाध्यक्ष (श्री टी.एन. चतुर्वेदी) : मैं अवश्य कहूंगा कि सरकार इस बारे में उत्तर प्रदेश सरकार से पता लगाए।

श्री रमा शंकर कौशिक : श्रीमन्, बता भी दें।

SHRI C.P. THIRUNAVUKKARASU (Pondichery): Mr. Vice-Chairman, Sir, I support the bill. I welcome the Bill. The DMK wholeheartedly welcomes this Bill. Now, I would like to say something about the matrix of this amendment. The proposed amendment of article 335 of the Constitution is being made to remove the adverse effects of the Government Order dated 22nd July, 1997. The Scheduled Castes and the Scheduled Tribes had been enjoying the facility of relaxation of qualifying marks and standards of evaluation in matters of reservation in promotion.

The Supreme Court in its judgements in Indira Sawhney *versus* Union of India and S. Vinod Kumar *versus* Union of India has held that relaxation is not permissible under Article 16(4) in view of the power contained in Article 335 of the Constitution. In order to implement the directions of the Supreme Court, the Government of India issued an order on 22nd July, 1997 for removing the facilities enjoyed by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the relaxation of qualifying marks and standard of evaluation. After the withdrawal of the G.O., several Members of Parliament and several other organisations raised objections and shouted slogans in the streets against this ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI T.N. CHATURVEDI) : You have got only two minutes. It is better if you give your suggestions because we have to finish the whole debate on this Bill by 4 o'clock.

SHRI C.P. THIRUNAVUKKARASU : Yes Sir; I will finish in two minutes. In the Lok Sabha, this issue was raised on 17th and 18th March. The proceedings of the House were obstructed and disturbed. On that day, the Prime Minister said in the Lok Sabha, and I quote ..*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI T.N. CHATURVEDI) : You can leave that. This has already been quoted You wind up now.

SHRI C.P. THIRUNAVUKKARASU : Sir, I am sorry this portion has not been quoted. I would like to quote this now. I quote, "The Government is committed to maintain the system of reservation that has been followed so far and is proposed to bring forward a legislation and even to amend the Constitution, if so required." Sir, the Prime Minister on 15th March, 1999 said in the Convention of the Members of Parliament, and I quote, "The Government has already taken steps to review the operational guidelines issued by the Ministry of Personnel regarding the reservation in Government

jobs, which has created the discontent among the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. The Government is committed to protect the interests of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes employees and the operational guidelines issued will be withdrawn as quickly as possible." It is said and done by this Government.

THE VICE-CHAIRMAN(SHRI T.N. CHATURVEDI) : You have to wind up now.

SHRI C.P. THIRUNAVUKKARASU : Yes; Sir. Eminent jurists and some elite people are still criticising the amendment and canvassing that there should not be any reservation in promotion. They argue the judgement of the Supreme Court in Vinod Kumar and Indira Sawhney' case. ..*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI T.N. CHATURVEDI): But now it is coming. You have only to support it.

If you want to give any suggestions, you can give.

SHRI C.P. THIRUNAVUKKARASU : Sir, I am supporting it. This is my suggestion. ..*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI T.N. CHATURVDI): We can forget as to what others say. ..*(Interruptions)*...

SHRI C.P. THIRUNAVUKKARASU : They say, "it is against national interest. Merit alone has to be considered." Why I am saying this is because even today it is lingering in the minds of the people that merit alone has to be taken into consideration; this amendment is not for national interest. I would say that these promotions and selections are pending from the year 1947. From the year 1958, these facts have to be taken into consideration for giving promotions, and relaxation has to be given. For the past 52 years this has been so and nothing has happened against the national interest by adopting this policy. So, there should not be any bar at all in giving relaxation to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes even today. Then I would like to say that Tamil Nadu is mainly responsible and has played a pioneer role in the development of the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other backward classes. To safeguard the interests of the deprived or the depressed society, the then Madras Government had set up grants-in-aid to regulate financial aid to the educational institutions for the depressed classes. This happened in the year 1885. In the year 1921, the State Council of Madras passed a

resolution ..*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI T.N. CHATURVEDI): Why are you going into the history? You straightaway come to the suggestions because there is no time. Your time is already over..*(Interruptions)*...

SHRI C.P. THIRUNAVUKKARASU : I am sorry. I may please be permitted. I am winding up in two minutes. Only two persons are speaking from our side. ..*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI T.N. CHATURVEDI) : There are a large number of 'Other Members' who have to speak. We would like to hear you later on.

SHRI C.P. THIRUNAVUKKARASU : I will finish in two minutes. From the year 1921, we are doing it. The DMK is for this proposal. When the DMK became part and parcel of NDA Government, it was said and propagated from various platforms that as far as the BJP Government is concerned, it is against the backward communities, it is against the Scheduled Caste and Scheduled Tribe communities, it is against the minorities; and along with the BJP, the DMK has also been criticised like anything on this issue. But by bringing three amendments to the Constitution, the NDA Government has ultimately proved that it is not against the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and minorities. Sir, one amendment is with respect to the backlog, another amendment is related to extending the period of reservation for the next ten years. And the third amendment is related to giving relaxation to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in promotion.

So, this proves that as far as the NDA Government is concerned, it is not against backward classes or the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes. This is the point. This is the thing that I am stressing. All along, they are saying that the DMK has one policy and the BJP has another policy. As far as backward classes, the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and minorities are concerned, we are sailing in the same boat. So, I welcome the Bill and support the Bill.

Thank you very much.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI T. N. CHATURVEDI): Mr. Margabandu, one minute. Probably, you don't want to use it.

SHRI R. MARGABANDHU (Tamil Nadu): Sir, I am supporting this Bill. After the recommendations of the Mandal Commission regarding

backward classes and other things, my suggestion would be that the backward classes should also be included in article 335.

Then, Sir, as far as promotion is concerned, qualifying exemption and evaluation standards are the two criteria. As a matter of fact, I would like to quote my personal experience in this matter. When I was the Managing Director of the Textbook Society in Tamil Nadu in 1988, I gave promotion to a Harijan lady officer in the Textbook Society, but the institution opposed it. The matter was taken to the High Court and challenged. When the less privileged persons from the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes are given concessions in qualification, the same concession has to be extended to equally less privileged backward class people also.

I have one more suggestion. Now, 50 years after the Independence, the Government must think of raising the standard of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes people to that of other communities so that they can be placed well and equally in the society. There is one paragraph in Indira Sawhney's case. It reads:

> "In providing for the reservation and the appointment to posts under article 16(4), the State has to take into consideration the claims of the members of the backward classes consistently with the maintenance of the efficiency of the administration."

So, maintenance of the efficiency of the administration is also to be taken into consideration while considering this Bill.Thank you.

उपसभाध्यक्ष (श्री टी.एन. चतुर्वेदी) : श्री मूल चन्द मीणा, 5 मिनट में समाप्त कर दीजिए।

श्री मूल चन्द मीणा (राजस्थान) : कोशिश करूंगा महोदय।

उपसभाध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा लाए गए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सेवाओं में आरक्षण विधेयक, 2000 का मैं स्वागत करता हूं और इस बिल का समर्थन करता हूं। यह मैं जरूर कहना चाहूंगा कि देरी से सही पर सरकार ने इस बिल को लाकर अच्छा काम किया है। इससे शैड्यूल्ड कॉस्ट और शैड्यूल्ड ट्राईब्स के लोगों में जो गलत भावना पैदा हो गई थी, असुरक्षा की भावना पैदा हो गई थी उन लोगों में विश्वास वापिस जागा है कि सरकार से हमें सुरक्षा मिल जाएगी। इस प्रकार की भावना उन लोगों में जागी है। उपसभाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक को लाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि ...**(व्यवधान)**

उपसभाध्यक्ष (श्री टी.एन. चतुर्वेदी) : वह कह दिया है, आप केवल सजेशंस दे दीजिए।

श्री मूल चन्द मीणा : हां, सर मैं सजेशंस ही दे रहा हूं। 1993 के अंदर एक डिसीजन

आया था - पंजाब सरकार बनाम जुनेजा केस में कि पांच साल तक पदोन्नति के अंदर रिजर्वेशन दिया जा सकता है। लेकिन उस समय जो सरकार थी उसको शैड्यूल्ड कॉस्ट और शैड्यूल्ड ट्राईब्स के कर्मचारियों को प्रमोशन देने की जो नीति थी उसको बरकरार रखने के लिए संशोधन लाना पड़ा। उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की पीठ को यह जुनेजा केस दे दिया गया और उसमें जो डिसीजन हुआ वह किस आधार पर हुआ, उन जजों की नीति क्या थी, उनकी नीयत क्या थी उसके बारे में मैं कहना चाहूंगा। उन जजों ने जो उसका उदाहरण दिया है वह अमेरिकी कोर्ट के फैसले का उदाहरण दिया है ...

उपसभाध्यक्ष (श्री टी. एन. चतुर्वेदी): ऐसा है कि इसके ऊपर चार बजे वोटिंग होनी है, यह हाउस का मत है। इस वजह से फैसलों को छोड़कर आप सजेशन्स दे दीजिए।

श्री मूल चन्द मीणा : सर, मैं सजेशन्स ही दे रहा हूं। उसके बाद अनुसूचित जाति और जनजाति के सांसद भी प्रधान मंत्री जी से 1996 में मिले थे और उस समय प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। उन्होंने आश्वासन दिया था कि वह संशोधन बिल लायेंगे। आश्वासन के बाद भी बिल नहीं आया। उसके बाद 1998 में फिर प्रधान मंत्री जी ने आश्वासन दिया लेकिन फिर भी वह संशोधन विधेयक नहीं आया। उसके बाद दिसम्बर, 1999 में प्रधान मंत्री जी ने सांसदों को आश्वासन दिया और अब शीघ्र ही यह संशोधन बिल आ जाएगा। इससे हमको संतुष्टि हुई है। इसका प्रधान मंत्री जी बार-बार आश्वासन दे रहे थे, उनका वह आश्वासन भी पूरा हो रहा है। इस बिल के आने से शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के जितने लोग हैं, उनमें आशा की किरण जगी है। वे भी समझेंगे कि इस सरकार में हमारी सुरक्षा है, हमारा हित है। इसके साथ ही मैं सुझाव देना चाहूंगा।

1. आरक्षण नीति से संबंधित एक व्यापक कानून बनाना चाहिए।
2. आरक्षण संबंधी सभी नियम, विधि और आदेश व कानूनों को संविधान की नौंवी अनुसूची में रखा जाना चाहिए जिससे कि आरक्षण व्यवस्था और नीति सुचारु रूप से बिना किसी अवरोध के अनुपालित की जा सके।
3. किसी भी न्यायालय के समकक्ष आरक्षण संबंधी किसी भी मामले में अनुसूचित जाति, जनजाति आयोग की सलाह लेना आवश्यक हो।
4. आरक्षण संबंधी किसी भी आदेश को जारी करने से पहले अनुसूचित जाति, जनजाति आयोग की सलाह लेना अनिवार्य हो।
5. आरक्षण के मामले में ढील बरतना, आदेशों व नीतियों को तोड़-मरोड़कर प्रस्तुत करने वाले संबंधित अधिकारियों को दण्डित करने की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए।
6. अनुसूचित जाति, जनजाति आयोग को सलाह, प्रतिवेदन के ऊपर जांच करने और आदेश देने और उनकी अनुपालना कराने के न्यायिक अधिकार प्रदान किए जाएं।

उपसभाध्यक्ष महोदय, अभी शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्स आयोग ने कालेज के अन्दर प्रमोशन में गड़बड़ी करने के मामले की जांच के आदेश दिए थे और वहां के अधिकारियों को नोटिस देकर बुलाया गया था, लेकिन इस देश के अंदर न्यायालयों में ऐसी भावना के लोग बैठे हुए

हैं, जो दलित की बात नहीं करते हैं, शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्स की बात नहीं करते हैं, वे केवल अपनी भावनाओं के आधार पर, अपनी जाति के आधार पर ऐसे फैसले कर देते हैं। जिन अधिकारियों को हाईकोर्ट ने स्टे आर्डर दे दिया..

उपसभाध्यक्ष (श्री टी.एन. चतुर्वेदी): आप उस बात को छोड़ दीजिए। आप कोर्ट वगैरह की आलोचना छोड़ दीजिए।

श्री मूल चन्द मीणा: मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं। मैं तो वास्तविकता बता रहा हूं। उन लोगों की क्या नीयत है, क्या नीति है, क्या दृष्टिकोण है। मैं दृष्टिकोण की बात कह रहा हूं..

उपसभाध्यक्ष: हो गया, ठीक है। मैं आपकी बात मानता हूं कि आपने कोर्ट की आलोचना नहीं की है।

श्री मूल चन्द मीणा: शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों के लिए आरक्षित व्यवस्थाएं हैं। इसके कुछ अनुच्छेद हैं- 15(4), 16(3), 16(4), 16(4)(ए), 46, 309 और 335 इनको तोड़-मरोड़कर के इस प्रकार के निर्णय दे रहे हैं कि जो अधिकार शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को मिले हैं, उनको छीना जा रहा है। इसका अधिकार केवल संसद को होना चाहिए। राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर से यह अधिकार होना चाहिए। न्यायालय जो आदेश दे रहे हैं, अनुच्छेद 141 के अंदर कानून बनाकर उनका तुरन्त पालन किया जाना चाहिए क्योंकि इसका राजस्थान ज्यादा विक्टिम हुआ है। राजस्थान में शैड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्स के जो आईएएस और आईपीएस अधिकारी थे, उनको रिवर्ट किया गया है, इससे उनको ज्यादा आघात लगा है। मैं यह कहना चाहूंगा कि इस विधेयक के साथ ही इसमें यह क्लाज भी जोड़ी जाए कि जो अधिकारी या कर्मचारी रिवर्ट हुए हैं, उनको वापस उसी हालत में लाया जाए जैसी हालत में वे इससे पहले थे, मैं इस विधेयक के अंदर ऐसा प्रावधान चाहता हूं। इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI T.N. CHATURVEDI): Dr P. Selvie Das. You have only three minutes to speak.

DR. (MS.) P. SELVIE DAS (NOMINATED): Sir, I don't think I need even three minutes.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI T.N. CHATURVEDI): That will help others.

DR. (MS.) P. SELVIE DAS: Thank you for giving me an opportunity.

Sir, I strongly support and welcome the Bill. It should be implemented as early as possible.

Sir, I would like to point out just a few things. One is that, we do have entrance examinatrions for recruitments in certain institutions and organisations. I would like the Government set up as well as the private organisations to reduce the qualifying marks for the Scheduled Caste and

Scheduled Tribe candidates, wherever they have the entrance examination. Even today, in the Union Public Service Commission, they do have this system. If it is 50 marks prescribed for the general category candidates, it is 40 or 45 marks for the Scheduled Caste and Scheduled Tribe candidates. Even when they are calling them for an interview, they should take this into account. Secondly, if the Government really wants to achieve what we could not achieve in the last 53 years, we should be able to achieve it in a couple of years after we pass this Bill. That is, the backlog that we have of Scheduled Caste and Scheduled Tribe vacancies in all the organisations, both private and public sector as well as Government Departments. We should be able to fill them up. While implementing this order, if you get into any office, I am sure they are going to say, "We do not have positions. All are filled up." If they have to wait for that, it cannot be done. So, I would request the concerned Ministry, the Department of Personnel and Training, to issue a memorandum to all the Departments saying that they should be able to create supernumerary posts; otherwise it is impossible. Everywhere, all the posts would be filled up. If we could do that by creating supernumerary posts, it would be better and the finance involved also would be less. While, in the new recruitment - not the backlog, - the qualifying marks being reduced, we should be able to follow the roster system. It should be strictly followed in promotions also. But in certain States, in promotions, they have gone up to the first rank of the gazetted position. But I think we should take it to the higher levels also. I also request the Minister that the memorandum which has been issued by the Department of Personnel and Training should be withdrawn because, even today, many Departments are holding on to that memorandum and saying, "We cannot make the promotion." Thank you very much.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI T.N. CHATURVEDI): With this, you support the Bill.

SHRI V.P. DURAISAMY (Tamil Nadu): In the beginning itself, she said so.

उपसभाध्यक्ष (श्री टी.एन.चतुर्वेदी) : श्री गांधी आज़ाद। आप तीन मिनट ले लीजिए।

श्री गांधी आज़ाद (उत्तर प्रदेश) : धन्यवाद महोदय, मैं तीन मिनट ही लूंगा। महोदय, आरक्षण का मामला भीख का नहीं, भागीदारी का मामला है इसलिए मैं इस विधेयक का पुरजोर समर्थन करता हूं। महोदय, नियुक्ति में आज तक आरक्षण कहीं भी पूरा नहीं हुआ है क्योंकि कभी एबल, कभी सूटेबल और कभी ट्रेसेबल लैक्यूना लगाए गये, जिसके कारण आरक्षण पूरा नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त आरक्षण पूरा करने वालों की नीयत खराब होने के कारण भी आरक्षण आज भी

कहीं पूरा नहीं हो पाया। साथ-साथ न्यायालय द्वारा न्याय न होने के कारण भी प्रमोशन में जो आरक्षण 22 जुलाई 97 से रोक दिया गया था, मैं मंत्री महोदया से निवेदन करूंगा कि उस अन्याय से लोगों को बचाने के लिए यह प्रमोशन 22 जुलाई 97 से ही लागू किया जाए। इसके साथ-साथ मैं मांग करता हूं कि आरक्षण को संविधान की नौवीं अनुसूची में रखा जाए ताकि इस वर्ग के लोग न्यायालय के अन्याय का शिकार न हो सकें। इसके अतिरिक्त सभी वर्गों की सेवाओं में नियुक्ति एवं प्रमोशन्स में आरक्षण दिया जाए और बैकलॉग भी पूरा किया जाए। मैं यह भी मांग करता हूं कि सभी न्यायालयों, उच्च न्यायालयों तथा सर्वोच्च न्यायालय में भी आरक्षण देने की व्यवस्था की जाए। महोदय, जिस सदन से हम बोल रहे हैं, इस सदन में भी आरक्षण नहीं है और साथ ही साथ विधान परिषदों में भी आरक्षण नहीं है इसलिए मैं मंत्री महोदया से निवेदन करूंगा कि संविधान संशोधन विधेयक लाकर इस सदन में और विधान परिषदों में भी आरक्षण को लागू किया जाए। इसके अतिरिक्त निजी क्षेत्र जो सरकार द्वारा भारी ऋण और अनुदान लेकर संचालित होते हैं, उनमें भी आरक्षण की व्यवस्था की जाए। साथ ही साथ मैं अनुरोध करता हूं कि आरक्षण पूरा न करने वाले अधिकारी को भी कोई न कोई दंड देने की व्यवस्था की जाए ताकि आरक्षण का पूरा लाभ मिल सके। इसी मांग के साथ पुनः समर्थन करते हुए मैं अपनी बात को विराम देता हूं। धन्यवाद।

DR. ALLADI P. RAJKUMAR (Andhra Pradesh): Mr. Vice-Chairman, Sir, on behalf of my party and on my own behalf, I congratulate the Government on getting this Bill for discussion. We whole-heartedly support this Bill. Sir, these facilities which are being given to the SCs and STs are well-deserved. Still, the Government should have an open mind and think how best to give more facilities to these categories. In Andhra Pradesh, our hon. Chief Minister, Mr.Chandrababu Naidu, has launched a special drive to fill up all the vacancies of backlog in the State. My sincere appeal, through you, Mr. Vice-Chairman, to the Government is that the BCs should also be given the same facilities as are being given to the SCs and STs. I want to highlight this point for the BCs. With this, I whole-heartedly support this Bill. Thank you very much.

SHRI K.B. KRISHNA MURTHY (Karnataka): I thank you, Mr. Vice-Chairman, for giving me this opportunity to speak on the Constitution (Eighty-Eighth Amendment) Bill, 1999. The Union Government and many State Governments have not filled the backlog of vacancies meant for the SC and ST. This backlog was created by giving lame excuses of non-availability of candidates at the time of recruitment. The Government should ensure that the backlog vacancies are filled up. Even after 53 years of Independence, the SC and ST people have no proper representation in services like the judicial services, foreign services and scientific services. Somehow, they are avoided, with the dishonest intention of keeping them out of the total progress, and unless this disparity, this apathy, goes, these

downtrodden people will not be able to come up and join the mainstream of the society to build up this nation. So, the Government should ensure that in these services also, reservation is done, through this Amendment.

One last thing I want to mention, Sir. The Scheduled Castes and Scheduled Tribes throughout the nation have become apprehensive that the Constitution Review Committee constituted by the Government may extinguish the reservations and concessions enshrined in the Constitution by Dr.Babasaheb Ambedkar. I feel that the Constitution (Eighty-Eighth Amendment) Bill may remove their fears. But I still feel that the Government should make it clear that the Constitution Review Committee is not here to remove the reservations and concessions extended to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Sir, a Reservation Act should be passed by Parliament and all issues should be in one Act. With these words, I support this Bill. Thank you very much.

SHRI SHANKAR ROY CHOWDHURY (West Bengal): Mr. Vice-Chairman, Sir, I would like to place before the House certain issues of concern, as far as the Bill and the series of Bills which have been passed earlier are concerned. Firstly, it is an issue of concern that whereas the Supreme Court is the supreme authority in which the entire nation places its trust on all matters, whether political, constitutional, economic or otherwise, we are, today, by the passage of this Bill, the next Bill, as well as the previous Bill, utilising the legislative process to circumvent the Supreme Court. Is there something wrong with our process? Is there a conflict between the Supreme Court and the legislative process?

[THE DEPUTY CHAIRMAN in the Chair]

We should, I think, look into the reason why the Supreme Court, which is the highest judicial body of the land, having examined all the factors, chose to pass the opinion it did. And this thing, we should examine with an unbiased and unprejudiced approach.

The second area of concern is, even after 53 years of independence, why has the economic state of the Scheduled Castes/the Scheduled Tribes not come up? Where is the flaw? Is there a growing, so-called, creamy layer within the Scheduled Castes/the Scheduled Tribes themselves, which has got a vested interest in keeping the remainder of the Scheduled Castes/the Scheduled Tribes backward? What steps is the Government going to take to ensure that the fruits of all this legislation that we are discussing will finally get to the people for whom it is intended, and

not get absorbed by the increasing thickness of the creamy layer which is swarming within the Scheduled Castes themselves?

Thirdly, Madam Deputy Chairman; sorry, Chairperson ..*(Interruptions)*...

THE DEPUTY CHAIRMAN: I don't mind if you call me a man! It is okay. I am not so particular about it.

SHRI SHANKAR ROY CHOWDHURY: Madam, Mrs. Indira Gandhi was called the only man in the Cabinet!

DR. KARAN SINGH (Delhi): I object!

SHRI SHANKAR ROY CHOWDHURY: I think, Sir, you were in the Cabinet!

THE DEPUTY CHAIRMAN: It is a very chauvinistic statement that she was the only man. She was really the only woman.

SHRI SHANKAR ROY CHOWDHURY: Okay. Madam, my final point is, I would like to take advantage of this opportunity when the attention of the House is focussed on reservations, to project, before the House, the case of ex-servicemen. Whenever we proceed to the courts of law for relief, as far as ex-servicemen are concerned, we are often informed, the court often decides, that in view of the existing reservations for Scheduled Castes/Scheduled Tribes and Other Backward Classes, it is no longer possible for them to give the reservations which have been guaranteed for ex-servicemen. Through you, Madam, I would like to bring to the notice of the Government that this is the plight of the ex-servicemen who are not being given their due share in the race for reservations. Thank you very much.

SHRI EDUARDO FALEIRO (Goa) : Madam Deputy Chairperson, I support this Bill, and I want to draw the attention of the House, and also of the Government, to the commitment made by the former Law Minister, Shri Ram Jethmalani, that he would consider favourably the case of Christians of Scheduled Caste origin for the purpose of making Constitution amendments so that they get the benefit like the ones which we are considering at present. Now I hope and pray, though Mr. Jethmalani is no more the Law Minister, that the Government will abide and stand by the commitment made by him and, therefore, I urge upon the House to support

4.00 P.M.

the Government in bringing forward these Constitutional amendments so that the Christians of Scheduled Caste origin also get the benefits. They deserve; their condition is pitiable, miserable, it is unfortunate like their other brethren.

श्रीमती जमना देवी बारूपाल (राजस्थान) : उपसभापति जी, यह जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का बिल आ रहा है इसके लिए मैं प्रधान मंत्री जी और पूरे सदन का हृदय से आभार व्यक्त करती हूं। आज इनके उत्थान की बात कर रहे हैं, जब तक शोषित, दलित और गरीब को बराबर का दर्जा नहीं दिया जाएगा तब तक इनका आरक्षण तो रहना ही चाहिए। जब तक इनका जीवन स्तर दूसरो के बराबर नही होगा तब तक आरक्षण को रोकने का मुद्दा ही नहीं उठना चाहिए। आज भी उनकी पदोन्नति कभी तो जज साहब निरस्त कर देते हैं, कभी प्रमोशन रोक देते हैं। जैसे हमारे प्रदेश राजस्थान में हुआ, अधिकारियों की तीन-तीन, चार-चार साल से पदोन्नति रोक दी और वे दूसरे लोगो से बीस साल पीछे चले गए। जब तक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगो को आई.ए.एस, आई.पी.एस., आर.पी.एफ. और विश्वविद्यालयो में कुलपति और सभी जगह इन जातियो को बराबर का दर्जा नहीं दें, इनको समान स्तर पर नहीं रखें, तब तक इनको आरक्षण मिलना चाहिए। यदि हम उन्हें आरक्षण नहीं देते, मैं किसी जाति का नाम नही लेती लेकिन इनके जीवन के प्रति कुछ लोगो की सोच कीड़े-मकोड़ो से भी घटिया होती है। आज भी छुआछूत है, इन्हें घर बनाने के लिए कही जमीने नही मिल रही हैं। आज हमारे देश को आजाद हुए पचास साल से ऊपर होने जा रहे हैं लेकिन कुल मिलाकर इनकी दशा आज भी सोचनीय है। इसीलिए यह मुद्दा आया। हम इसके लिए आपका स्वागत करते हैं कि आरक्षण होना चाहिए और पदोन्नति में तो जरूर होना चाहिए। आपने मुझे बोलने का मौका दिया और मेरे दो शब्द सुने इसके लिए मैं सदन का धन्यवाद करती हूं। धन्यवाद।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now, we should have not less than two-thirds of the Members present and not less than half of the Members present and voting for it in the House. I want to put a proposal before the House and the Government that we have another Constitution Amendment Bill which we have to take up. It will not take much time. After the conclusion of the discussion on this Constitution (Eighty-eighth Amendment) Bill, 1999, we will start the discussion on the other Bill. After we finish that, we will have the voting on both the Bills, if the House so agrees. Otherwise, we will keep on adding more speakers on it and everything will be delayed. I want to put this proposal before the House and the Government.

SOME HON. MEMBERS: We agree.

SHRI SANGH PRIYA GAUTAM: You do what is legally and procedurally correct.

THE DEPUTY CHAIRMAN: There is nothing illegal about it. The thing is that we need, at least, 40 more Members to be present in the House. The Congress Party, the BJP and other parties have written that they have telephoned the Members to come over here. They will be coming.

SHRI SATISH PRADHAN (Maharashtra): Everybody supports this Bill.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Everybody wants to pass this Bill. There is no controversy about this Bill. But the thing is that the requisite number should be there. It has to be there. It is a pre-requisite. On the other Bill, there are only three speakers. संघ प्रिय जी, आप इस बिल पर बोल दीजिए लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप चालीस मिनट तक बोलेंगे।

श्री संघ प्रिय गौतम: उपसभापति महोदया, मैं पांच मिनट बोलूंगा। पहले तो मैं सरकार का, सदन का तथा राजनैतिक दलों का आभार व्यक्त करता हूं। इन शोषित, दलित, पीड़ित समाज के लोगों के प्रति सभी की हमदर्दी है, सभी इन पर दयालु हो रहे हैं और सर्वसम्मति से इस विधेयक को पारित कर रहे हैं। लेकिन मैं जो थोड़ी सी गलतफहमी है उसे भी दूर करना चाहता हूं। संविधान में आरक्षण दो तरह का है : एक तो लोकसभा तथा विधानसभा में तथा दूसरा नौकरियों मे। आर्टिकल 334 में नौकरियों के आरक्षण की कोई मियाद नही है, सबसे पहले मैं इसे ही स्पष्ट करना चाहूंगा। इस बारे में पूरे देश, पूरे समाज तथा सभी राजनीतिक दलों को गलतफहमी है। इसका कोई संबंध मियाद से नहीं है। भारत एक विकासशील देश और कल्याणकारी राज्य है। संविधान निर्माताओं ने इस देश के चतुर्मुखी विकास और जो हैव्ज हैं, सर्वहारा लोग हैं उनके कल्याण की बात कही थी। कल्याण का मतलब रोजी, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवा, सुरक्षा, न्याय, सम्मान तथा बराबरी है। यह जिन लोगों को नही मिली है उन्हें मिलनी चाहिए। यह जब तक नही मिलेगी तब तक हमारा देश कल्याणकारी देश नहीं रहेगा, इसमें किसी तरह की कोई गलतफहमी नही होनी चाहिए। आप सारे आंकड़े उठाकर देख ले, चाहे नौकरियों में देख लें या आर्थिक क्षेत्र अथवा सामाजिक क्षेत्र में देख लें तो पता चलता है कि हमारा मंतव्य पूरा नहीं होता।

मैं अधिक लंबी बात न कहकर एक प्रार्थना जरूर करना चाहूंगा कि हमारी जो विधायिका है, चाहे वह हमारे स्टेट लेजिस्लेचर्स हो, राज्य विधान मंडल हो या संसद हो, हम जितने भी कानून पारित करते हैं, उसमें जो हमारी दिशा होती है वह विकास और कल्याण के क्षेत्र में होती है। उसमें जो हमारी कार्यपालिका है उसका यह परम कर्तव्य है कि वह उसका क्रियान्वयन उसी दिशा में करे। यह कार्यपालिका का दायित्व है, संवैधानिक दायित्व है। मैं इसके बारे में बहुत सी नजीरें भी दे सकता हूं। लेकिन तकलीफ तब होती है जब उसका इम्पलीमेंटेशन नही होता, क्रियान्वयन नहीं होता और दशा नहीं सुधरती है। मैं मीडिया के माध्यम से अपनी न्यायपालिका से प्रार्थना करता हूं कि उसका दायित्व है कि लेजिस्लेशन को उसी दिशा मे अनुवादित करना यानी विकास और कल्याण की दिशा में अनुवादित करना। न्यायपालिका से हमें यह उम्मीद नही है कि वह उसके विपरीत न्याय दे। इसमें कार्यपालिका द्वारा ऐसा हुआ है इसलिए आज यह नौबत आई

है। इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूं क्योंकि तरह तरह की शंकायें उत्पन्न होती है। आज सारे देश की परिस्थिति, सारे देश के लोगों की मानसिकता और सारे देश के राजनैतिक दलों का एक जुट होना और इस वर्ग के लिए सर्वसम्मति से राय बनाकर इस विधेयक को पारित करना यह एक शुभ संकेत हैं। मुझे आशा है कि इस देश का यह कानून इस देश की न्यायपालिका सहर्ष स्वीकार करेंगी और आगे चलकर किसी प्रकार की कोई बाधा इस विधेयक के कार्यान्वयन में नहीं आएगी। इन शब्दों के साथ उपसभापति महोदय, मैं अपनी सरकार, प्रधानमंत्री और मंत्री महोदया का आभार प्रदर्शित करते हुए इस विधेयक का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

SHRI H.K. JAVARE GOWDA (Karnataka): Madam, I support this Bill. The Scheduled Castes and the Scheduled Tribes people are the deprived classes of our society. To protect them from social injustice and other forms of exploitation, this Bill must be passed. Thank you.

THE DEPUTY CHAIRMAN: That is all. When we want you to speak, you don't speak. When we do not want you to speak, you keep on speaking.

***मिर्जा अब्दुल रशीद** (जम्मू और कश्मीर) : मैं इस बिल का पुरजोर सपोर्ट करता हूं जो एससी और एसटी के सिलसिले में डिसकस हो रहा है। मैं सिर्फ आपके वसातत से इस हाउस का तवज्जह दिलाना चाहता हूं कि जम्मू-कश्मीर सरकार की तीन मुखतलिफ सरकारों ने जम्मू-कश्मीर के पहाड़ी स्पीकिंग ट्राइब्स का बाकायदा सर्वे करने के बाद रेकमंड किया है कि उनको भी एसटी डिक्लेयर किया जाए। मैं आपके विसातत से इस हाउस के सामने गवर्नमेंट से गुजारिश करूंगा कि यह जो केस इस वक्त सेंट्रल सरकार के पास है और जिसे जम्मू-कश्मीर के पहाड़ी स्पीकिंग ट्राइब के लिए बाकायदा सर्वे करने के बाद तीन सरकार ने जिसे रेकमेंड किया है कि इनको भी एसटी का दर्जा दिया जाए उसको वह मंजूर करे।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now I have no other alternative. The discussion on the Constitution (Eighty-Eighth) Amendment Bill, 1999 is over. We will have the voting when we have the requisite number. Till then the House cannot sit in a vacuum. Now the Minister will reply to the debate. After that we will take up the Constitution (Eighty-Sixth) Amendment Bill, 1999. आपका यह पहला कांस्टिटयूशन अमेंडमेंट बिल है?

श्रीमती वसुन्धरा राजे : नहीं नहीं। इस विषय पर पहले भी हो चुका है।

SHRIMATI VASUNDHARA RAJE: Madam, it is a matter of great satisfaction for me to witness the overwhelming response of the Members in support of the move of the Government for this Constitutional Amendment.

---

*Transliteration of the speech in Persian script is available in the Hindi version of the Debate.

Madam, as stated by the hon. Prime Minister in the Lok Sabha on March 18, 1999, the Government had initiated A review of the five Office Memoranda which were issued by the Department of Personnel and Training between January and August, 1997. As the House is aware, the Government had, earlier, in the last Session of Parliament, introduced a Constitutional Amendment Bill to overcome the adverse effect of the O.M. dated August 29, 1997 towards fulfilment of the promise of the hon. Prime Minister. With the support of this House and that of the other House, the Constitution was amended to incorporate article 16 (4B) vide the Constitution (Eighty-First Amendment) Act, 2000. The Members would be pleased to know that the Government has already issued orders on July 20, 2000 for excluding the backlog vacancies from the 50 per cent ceiling which had been imposed earlier in August, 1997, in implementation of a Supreme Court judgement. As far as the other three O.Ms are concerned, I would like to quickly go through those also. As per the O.M. dated January 30, 1997, based on the Supreme court judgement in the case of Birpal Singh Chauhan, if a SC/ST candidate had been promoted earlier, by virtue of the rule of reservation/roster, than his senior general candidate, and the senior general candidate has been promoted later on, in deciding the higher grade, the general candidate would get the seniority over such earlier promoted SC/ST candidate. The Five-Judge Constitution Bench of the Supreme Court has since reaffirmed the earlier judgement in the Birpal Singh Chauhan case. It has been decided to await the outcome of the petition pending in the Supreme Court on the contents of article 16 (4A) of the Constitution. And in another petition challenging the inclusion of the Tamil Nadu Act (45) of 1994 in the Ninth Schedule of the Constitution, as per the O.M. dated July 2, 1997, based on the Supreme Court Judgement in the R.K. Sabharwal's case, the reservation has to be related to posts and not to vacancies; accordingly, the vacancy-based roster was replaced by post-based roster. The advice of the Attorney-General, in this matter, has been obtained and the issue is at an advanced stage of consideration. As far as the O.M. dated August 13, 1997, consequent to the Supreme Court judgement in the Indira Sawhney case, the memorandum issued in pursuance of article 16 (4A) of the Constitution continues reservation in promotion for SCs and STs beyond 15.11.1997. But for this memorandum, reservation and promotion would have ceased to exist after 15.11.1997 in terms of the Supreme Court judgement in the Indira Sawhney case. It has been decided to await the outcome of the petition pending in the Supreme court on the contents of article 16 (4A) of the Constitution. Hence, the present Bill is another step

taken by this Government, in fulfilment of the promise of the hon. Prime Minister in regard to the O.M dated July 22, 1997 that was issued, in implementation of the Supreme Court Judgement in the case of S.Vinod Kumar vs. Union of India. The move also reflects the prime concern of the Government towards the cause of welfare of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

The ambit of reservation policy is very wide and the Members have raised various points touching different aspects of the reservation policy. I appreciate the concern of the Members for the welfare of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. I would like to quickly go through some of the points that have been made by them. Dr. Faguni Ram has welcomed the Bill and I thank him for that. He has said that this Bill would accelerate the promotion of SC and ST candidates. And I have taken note of the points which have been raised by the hon. Member. Shri Ram Nath Kovind was saying that the legislation on reservation should be kept outside the purview of the courts.

Here, I would like to mention that a legislation of this type and its inclusion in the Ninth Schedule is not considered desirable for some reasons. The prime reason among them is that the Supreme Court has, during the last few years, given a number of judgments on, and interpretations of, the provisions of the Constitution and the Government has been considering steps to overcome the adverse effect of these judgments in view of the five OMs issued by this Department between January and August 1997. The legal validity of the instructions has specifically been upheld by the Supreme Court in the Indira Sawhney case. The executive instructions issued by the DOPT, derived from Article 16(4) of the Constitution, come within the meaning of law. No legal deficiency has been apprehended in the implementation of the policy. Executive instructions have the advantage of flexibility to meet the emerging needs and such flexibility could not always be provided by legislative enactment, and flouting of executive instructions on reservation amounts to misconduct, making the delinquent official liable to disciplinary action against the Conduct Rules, and the legislation on reservation made by the Government of Tamil Nadu and included in the Ninth Schedule is already challenged in the Supreme Court. The Tamil Nadu Government has made an application for early hearing and it will be quite advisable to await the outcome of that.

As far as Shri Ram Deo Bhandari is concerned, he has highlighted the point about the backlog of vacancies. This will be taken care of by the

last Constitutional Amendment under which backlog of vacancies can now be fulfilled beyond the 57% reservation mark. Again, he mentioned about relaxation in qualifying marks and standards. It will be appreciated that the amendment to the Constitution, as proposed through this Bill, cannot be done retrospectively. Then, there was a point raised by him about reservations in judiciary. The National Convention of SC/ST MPs had also made this recommendation. The Department of Justice had been consulted and as per articles 233, 234 and 235 of the Constitution, matters relating to appointment, promotion and posting of persons in district and subordinate judiciary are within the purview of the respective State Governments and the High Courts. No provision exists in the Constitution of India for reservation in respect of any class or category of persons for appointment as judges of High Courts and Supreme Court.

Shri Khagen Das has supported the Bill. I thank him very much. He has talked about land being taken away from the SCs and the STs. I am sure this point is being taken care of by the Department of Rural Development while dealing with the issue of land reforms. Then, Shri Thirunavukkarasu has also supported the Bill and I thank him. The proposed amendment would accelerate the promotion of SC/ST candidates as there are now relaxed standards that have been provided. Shri Margabandu raised the point about the OBCs. The question of extending the provisions of the Bill to the Backward Classes does not arise as there is no reservation in promotion for the Other Backward Classes. Shri Moolchand Meena has said that the National Commission for SCs and STs should be consulted in all matters concerning reservation. The Commission is already consulted on all major policy matters in terms of articles 338 and 339 of the Constitution. You have also talked about comprehensive legislation in the Ninth Schedule, to which I have already replied. You have also asked for penal action against defaulting officers. Such action can be taken against defaulting officers under the relevant Conduct Rules and instructions relating to reservation have the force of law and their violation is taken very seriously. You did mention the fact that you were very appreciative of the fact that the Prime Minister has finally brought this Bill. I am happy to say that in the 13 days that he was in power, he made a promise and within the 13 months of his coming back to power, he has fulfilled that promise which is, I believe, more than, I can say, what most other Governments did. As far as Dr. Selvie Das is concerned, she has supported the Bill and I thank her very much for it. She has suggested lower qualifying marks for SCs and STs. This would be achieved in a way

now. After the Constitution amendment, lower qualifying marks in direct recruitment are already permissible. I also thank Mr. Gandhi Azad and Mr. Alladi P. Rajkumar for their very valuable contribution. I also thank Shri K. B. Krishna Murthy. You have said that the Government should ensure filling up of the backlog of vacancies. This will be done through the OM of 20th July. You have spoken about reservation in judiciary and a comprehensive legislation on reservations to which I have already replied earlier. You have also spoken about issuing of orders for filling up of the backlog vacancies. As I said, orders have been issued on 27th. As far as General Shankar Roy Chowdhury's point is concerned, he wanted to know whether there is any conflict between the Judiciary and the Legislature. No, Sir, there is no conflict between the two. The Bill has been brought in to fulfil the aspirations of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in getting accelerated promotions. I thank Shri Eduardo Faleiro for his valuable contribution. I also thank Jamunadeviji, Sangh Priya Gautamji, Javare Gowdaji and Mirza Abdul Rashid ...*(Interruptions)*... Thank you all very much for your useful contribution to the debate.

Madam, finally, I would only say that the Members would appreciate that the scope of this Bill is limited to restoring the relaxations of qualifying marks in standards of evaluation and matters of promotion. I, therefore, request the Members to extend their support to the Government in passing the proposed Constitution (Eighty-eighth Amendment) Bill so that the persons from the Scheduled Castes and Scheduled Tribes communities restart enjoying the benefits of relaxations which were available to them before the issue of the Memorandum dated 22nd July, 1997. With these words, Madam, I would commend the Bill for passage by this House.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I am happy that you thanked everybody while replying to the debate because we needed this breathing time. I am happy to announce that there are requisite number of Members present in the House. ...*(Interruptions)*... Where is the Minister of Parliamentary Affairs? ...*(Interruptions)*...He should also come because he is a Member of this House. ...*(Interruptions)*... I was worried because I was counting all the time, and the Members were going out. My calculations were going haywire. So, I was going to announce that 'please don't leave your seat' because my mathematics is at a stretch. ...*(Interruptions)*...

I shall now put the motion for consideration of the Bill to vote.

THE DEPUTY CHAIRMAN: The question is:

That the Bill further to amend the Constitution of India, be taken into consideration."

The House divided.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Ayes - 140

Noes - Nil

Ayes -140

Shri Parmeshwar Kumar Agarwalla

Shri S. Agniraj

Shri S.S. Ahluwalia

Shri Akhilesh Das

Shri Anil Kumar

Shri B.P. Apte

Shri Gandhi Azad

Shri Gulam Nabi Azad

Shri Bachani Lekhraj

Shri Santosh Bagrodia

Shri Balkavi Bairagi

Shrimati Jamana Devi Barupal

Shri Nilotpal Basu

Prof. Ram Deo Bhandary

Shri Hansraj Bhardwaj

Shri Karnendu Bhattacharjee

Shri Manoj Bhattacharya

Sardar Balwinder Singh Bhundar

Shri S.R. Bommai

Shri Drupad Borgohain

Shrimati Chandresh Kumari

Shri T.N. Chaturvedi

Shri S.B. Chavan

Shri Khagen Das

Dr. M.N. Das

Dr. (Ms.) P. Selvie Das

Dr. Biplab Dasgupta

Shri Anantray Devshanker Dave

Shri Sukh Dev Singh Dhindsa

Shrimati Saroj Dubey

Shri V.P. Duraisamy

Dr. Faguni Ram

Shri Eduardo Faleiro

Shri Oscar Fernandes

Shri Sangh Priya Gautam

Shri R. P. Goenka

Shri H.K. Javare Gowda

Shri Vedprakash P. Goyal

Shri Hiphei

Shri C.M. Ibrahim

Shri Arun Jaitley

Shri M.A. Kadar

Shri Kanshi Ram

Dr. Karan Singh

Shri Swaraj Kaushal

Shri Rama Shanker Kaushik

Shri Suresh A. Keshwani

Shri Aimaduddin Ahmad Khan (Durru)

Shri K.M. Khan

Shri K. Rahman Khan

Shri Ramachandra Khuntia

Dr. A.R. Kidwai

Shri Ram Nath Kovind

Shri Lachhman Singh

Prof. A. Lakshmisagar

Shri Pramod Mahajan

Shri Mahendra Prasad

Shri Bhagatram Manhar

Shri O.S. Manian

Dr. Manmohan Singh

Shri R. Margabandhu

Shri Md. Salim

Shri Moolchand Meena

Shri Ranganath Misra

Shri Dipankar Mukherjee

Shri Pranab Mukherjee

Shri K.B. Krishna Murthy

Shri M. Rajasekara Murthy

Dr. Y. Radhakrishna Murty

Shrimati Jayaprada Nahata

Shri M. Venkaiah Naidu

Shri S.Niraikulathan

Shri Sanjay Nirupam

Shri Onward L. Nongtdu

Shri Suresh Pachouri

Shrimati Chandra Kala Pandey

Shri Raju Parmar

Dr. A. K. Patel

Shri S. Ramachandran Pillai

Shri C.O. Poulose

Shri Satish Pradhan

Shri Ravi Shankar Prasad

Shri Balbir K. Punj

Shri Abdul Gaiyur Qureshi

Shri V.V. Raghavan

Shrimati Kum Kum Rai

Shri Lajpat Rai

Shrimati Bimba Raikar

Shri O. Rajagopal

Dr. Alladi P. Rajkumar

Shri C. Ramachandraiah

Shri Cho S. Ramaswamy

Shri K. Kalavenkata Rao

Shri K. Rama Mohana Rao

Mirza Abdul Rashid

Prof. (Shrimati) Bharati Ray

Miss Mabel Rebello

Shri Nabam Rebia

Shri Solipeta Ramachandra Reddy

Shri Abani Roy

Shri Ramachandraiah Rumandla

Shri K.M. Saifullah

Shri N.K.P. Salve

Shri Manmohan Samal

Prof. M. Sankaralingam

Shrimati Basanti Sarma

Shri Bratin Sengupta

Shrimati Savita Sharda

Shri Sharief-Ud-Din Shariq

Dr. Mahesh Chandra Sharma

Shri Arun Shourie

Shri Rajeev Shukla

Shri Arjun Singh

Shri Birabhadra Singh

Shri Devi Prasad Singh

Shri Jaswant Singh

Shri Raj Mohinder Singh

Shri Rajiv Ranjan Singh

Shri W. Angou Singh

Shri B.P. Singhal

Shri Rama Muni Reddy Sirigireddy

Shri P.N. Siva

Shri S. Sivasubramanian

Shri Gopalsinh G. Solanki

Shrimati Ambika Soni

Shri P. Soundararajan

Shri Ka. Ra. Subbian

Shri N. Thalavai Sundaram

Shri Rajnath Singh 'Surya'

Shrimati Sushma Swaraj

Shri C.P. Thirunavukkarasu

Miss Frida Topno

Shri Suryabhan Patil Vahadane

Shrimati Vanga Geetha

Prof. R. B. S. Varma

Shri A. Vijaya Raghavan

Shri S. Viduthalai Virumbi

Shri Ranjan Prasad Yadav

Shri Vijay Singh Yadav

Shri Khan Ghufran Zahidi

Noes - Nill

The motion was carried by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than two-thirds of the Members present and voting.

THE DEPUTY CHAIRMAN: The question is:

"That clause 2 stand part of the Bill."

The House divided.

THE DEPUTY CHAIRMAN:	Ayes	-	140
	Noes	-	Nil

Ayes - 140

Shri Parmeshwar Kumar Agarwalla

Shri S. Agniraj

Shri S.S. Ahluwalia

Shri Akhilesh Das

Shri Anil Kumar

Shri B.P. Apte

Shri Gandhi Azad

Shri Gulam Nabi Azad

Shri Bachani Lekhraj

Shri Santosh Bagrodia

Shri Balkavi Bairagi

Shrimati Jamana Devi Barupal

Shri Nilotpal Basu

Prof. Ram Deo Bhandary

Shri Hansraj Bhardwaj

Shri Karnendu Bhattacharjee

Shri Manoj Bhattacharya

Sardar Balwinder Singh Bhundar

Shri S.R. Bommai

Shri Drupad Borgohain

Shrimati Chandresh Kumari

Shri T.N. Chaturvedi

Shri S.B. Chavan

Shri Khagen Das

Dr. M.N. Das

Dr. (Ms.) P. Selvie Das

Dr. Biplab Dasgupta

Shri Anantray Devshanker Dave

Shri Sukh Dev Singh Dhindsa

Shrimati Sa.oj Dubey

Shri V.P. Duraisamy

Dr. Faguni Ram

Shri Eduardo Faleiro

Shri Oscar Fernandes

Shri Sangh Priya Gautam

Shri R. P. Goenka

Shri H.K. Javare Gowda

Shri Vedprakash P.Goyal

Shri Hiphei

Shri C.M. Ibrahim

Shri Arun Jaitley

Shri M.A. Kadar

Shri Kanshi Ram

Dr. Karan Singh

Shri Swaraj Kaushal

Shri Rama Shanker Kaushik

Shri Suresh A. Keshwani

Shri Aimaduddin Ahmad Khan (Durru)

Shri K.M. Khan

Shri K. Rahman Khan

Shri Ramachandra Khuntia

Dr. A.R. Kidwai

Shri Ram Nath Kovind

Shri Lachhman Singh

Prof. A. Lakshmisagar

Shri Pramod Mahajan

Shri Mahendra Prasad

Shri Bhagatram Manhar

Shri O.S. Manian

Dr. Manmohan Singh

Shri R. Margabandu

Shri Md. Salim

Shri Moolchand Meena

Shri Ranganath Misra

Shri Dipankar Mukherjee

Shri Pranab Mukherjee

Shri K.B. Krishna Murthy

Shri M. Rajasekara Murthy

Dr. Y. Radhakrishna Murty

Shrimati Jayaprada Nahata

Shri M. Venkaiah Naidu

Shri S. Niraikulathan

Shri Sanjay Nirupam

Shri Onward L. Nongtdu

Shri Suresh Pachouri

Shrimati Chandra Kala Pandey

Shri Raju Parmar

Dr. A. K. Patel

Shri S. Ramachandran Pillai

Shri C.O. Poulose

Shri Satish Pradhan

Shri Ravi Shankar Prasad

Shri Balbir K. Punj

Shri Abdul Gaiyur Qureshi

Shri V.V. Raghavan

Shrimati Kum Kum Rai

Shri Lajpat Rai

Shrimati Bimba Raikar

Shri O. Rajagopal

Dr. Ailadi P. Rajkumar

Shri C. Ramachandraiah

Shri Cho S. Ramaswamy

Shri K. Kalavenkata Rao

Shri K. Rama Mohana Rao

Mirza Abdul Rashid

Prof. (Shrimati) Bharati Ray

Miss Mabel Rebello

Shri Nabam Rebia

Shri Solipeta Ramachandra Reddy

Shri Abani Roy

Shri Ramachandraiah Rumandla

Shri K.M. Saifullah

Shri N.K.P. Salve

Shri Manmohan Samal

Prof. M. Sankaralingam

Shrimati Basanti Sarma

Shri Bratin Sengupta

Shrimati Savita Sharda

Shri Sharief-Ud-Din Shariq

Dr. Mahesh Chandra Sharma

Shri Arun Shourie

Shri Rajeev Shukla

Shri Arjun Singh

Shri Birabhadra Singh

Shri Devi Prasad Singh

Shri Jaswant Singh

Shri Raj Mohinder Singh

Shri Rajiv Ranjan Singh

Shri W. Angou Singh

Shri B.P. Singhal

Shri Rama Muni Reddy Sirigireddy

Shri P.N. Siva

Shri S. Sivasubramanian

Shri Gopalsinh G. Solanki

Shrimati Ambika Soni

Shri P. Soundararajan

Shri Ka. Ra. Subbian

Shri N. Thalavai Sundaram

Shri Rajnath Singh 'Surya'

Shrimati Sushma Swaraj

Shri C.P. Thirunavukkarasu

Miss Frida Topno

Shri Suryabhan Patil Vahadane

Shrimati Vanga Geetha

Prof. R. B. S. Varma

Shri A. Vijaya Raghavan

Shri S. Viduthalai Virumbi

Shri Ranjan Prasad Yadav

Shri Vijay Singh Yadav

Shri Khan Ghufran Zahidi

Noes- Nil

The motion was carried by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than two-thirds of the Members present and voting.

Clause 2 was added to the Bill.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now, I will take up Clause 1. There is one amendment by Shrimati Vasundhara Raje.

Clause-1 - Short Title

SHRIMATI VASUNDHARA RAJE: Madam, I move:

(2) That at page 1, line 3 *for* the words, brackets and figure "(Eighty-eighth Amendment) Act, 1999" the words, brackets and figure "(Eighty-second Amendment) Act, 2000' be *substituted.*

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now, I shall put Amendment (No. 2) moved by Smt. Vasundhara Raje to vote. The question is:

(2) That at page 1, line 3, for the words, brackets and figure "(Eighty-eighth Amendment) Act, 1999" the words, brackets and figure "(Eighty-second Amendment) Act, 2000' be *substituted.*

The House divided

THE DEPUTY CHAIRMAN: Ayes - 140

Noes - Nil

Ayes - 140

Shri Parmeshwar Kumar Agarwalla

Shri S. Agniraj

Shri S.S. Ahluwalia

Shri Akhilesh Das

Shri Anil Kumar

Shri B.P. Apte

Shri Gandhi Azad

Shri Ghulam Nabi Azad

Shri Bachani Lekhraj

Shri Santosh Bagrodia

Shri Balkavi Bairagi

Shrimati Jamana Devi Barupal

Shri Nilotpal Basu

Prof. Ram Deo Bhandary

Shri Hansraj Bhardwaj

Shri Karnendu Bhattacharjee

Shri Manoj Bhattacharya

Sardar Balwinder Singh Bhundar

Shri S.R. Bommai

Shri Drupad Borgohain

Shrimati Chandresh Kumari

Shri T.N. Chaturvedi

Shri S.B. Chavan

Shri Khagen Das

Dr. M.N. Das

Dr. (Ms.) P. Selvie Das

Dr. Biplab Dasgupta

Shri Anantray Devshanker Dave

Shri Sukh Dev Singh Dhindsa

Shrimati Saroj Dubey

Shri V.P. Duraisamy

Dr. Faguni Ram

Shri Eduardo Faleiro

Shri Oscar Fernandes

Shri Sangh Priya Gautam

Shri R. P. Goenka

Shri H.K. Javare Gowda

Shri Vedprakash P.Goyal

Shri Hiphei

Shri C.M. Ibrahim

Shri Arun Jaitley

Shri M.A. Kadar

Shri Kanshi Ram

Dr. Karan Singh

Shri Swaraj Kaushal

Shri Rama Shanker Kaushik

Shri Suresh A. Keshwani

Shri Aimaduddin Ahmad Khan (Durru)

Shri K.M. Khan

Shri K. Rahman Khan

Shri Ramachandra Khuntia

Dr. A.R. Kidwai

Shri Ram Nath Kovind

Shri Lachhman Singh

Prof. A. Lakshmisagar

Shri Pramod Mahajan

Shri Mahendra Prasad

Shri Bhagatram Manhar

Shri O.S. Manian

Dr. Manmohan Singh

Shri R. Margabandu

Shri Md. Salim

4522RS F—47-A

Shri Moolchand Meena

Shri Ranganath Misra

Shri Dipankar Mukherjee

Shri Pranab Mukherjee

Shri K.B. Krishna Murthy

Shri M. Rajasekara Murthy

Dr. Y. Radhakrishna Murty

Shrimati Jayaprada Nahata

Shri M. Venkaiah Naidu

Shri S.Niraikulathan

Shri Sanjay Nirupam

Shri Onward L. Nongtdu

Shri Suresh Pachouri

Shrimati Chandra Kala Pandey

Shri Raju Parmar

Dr. A. K. Patel

Shri S. Ramachandran Pillai

Shri C.O. Poulose

Shri Satish Pradhan

Shri Ravi Shankar Prasad

Shri Balbir K. Punj

Shri Abdul Gaiyur Qureshi

Shri V.V. Raghavan

Shrimati Kum Kum Rai

Shri Lajpat Rai

Shrimati Bimba Raikar

Shri O. Rajagopal

Dr. Alladi P. Rajkumar

Shri C. Ramachandraiah

Shri Cho S. Ramaswamy

Shri K. Kalavenkata Rao

Shri K. Rama Mohana Rao

Mirza Abdul Rashid

Prof. (Shrimati) Bharati Ray

Miss Mabel Rebello

Shri Nabam Rebia

Shri Solipeta Ramachandra Reddy

Shri Abani Roy

Shri Ramachandraiah Rumandla

Shri K.M. Saifullah

Shri N.K.P. Salve

Shri Man Mohan Samal

Prof. M. Sankaralingam

Shrimati Basanti Sarma

Shri Bratin Sengupta

Shrimati Savita Sharda

Shri Sharief-Ud-Din Shariq

Dr. Mahesh Chandra Sharma

Shri Arun Shourie

Shri Rajeev Shukla

Shri Arjun Singh

Shri Birabhadra Singh

4522RS F—48-B

Shri Devi Prasad Singh

Shri Jaswant Singh

Shri Raj Mohinder Singh

Shri Rajiv Ranjan Singh

Shri W. Angou Singh

Shri B.P. Singhal

Shri Rama Muni Reddy Sirigireddy

Shri P.N. Siva

Shri S. Sivasubramanian

Shri Gopalsinh G. Solanki

Shrimati Ambika Soni

Shri P. Soundararajan

Shri Ka. Ra. Subbian

Shri N. Thalavai Sundaram

Shri Rajnath Singh 'Surya'

Shrimati Sushma Swaraj

Shri C.P. Thirunavukkarasu

Miss Frida Topno

Shri Suryabhan Patil Vahadane

Shrimati Vanga Geetha

Prof. R. B. S. Varma

Shri A. Vijaya Raghavan

Shri S. Viduthalai Virumbi

Shri Ranjan Prasad Yadav

Shri Vijay Singh Yadav

Shri Khan Ghufran Zahidi

Noes - Nill

The motion was carried by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than two thirds of the Members present and voting.

Clause 1, as amended, was added to the Bill.

Enacting Formula

THE DEPUTY CHAIRMAN: There is one amendment by Shrimati Vasundhara Raje.

SHRIMATI VASUNDHARA RAJE: Madam, I move:

(1) That at page 1, line 1, *for* the word "Fiftieth" the word "Fifty-first be *substituted*.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now, I shall put Amendment (No.1) moved by Shrimati Vasundhara Raje to Vote. The question is:

(1) That at page 1, line 1, *for* the word "Fiftieth" the word "Fifty-first" be *substituted*.

The House divided

THE DEPUTY CHAIRMAN: Ayes -140

Noes - Nil

Ayes - 140

Shri Parmeshwar Kumar Agarwalla

Shri S. Agniraj

Shri S.S. Ahluwalia

Shri Akhilesh Das

Shri Anil Kumar

Shri B.P. Apte

Shri Gandhi Azad

Shri Gulam Nabi Azad

Shri Bachani Lekhraj

Shri Santosh Bagrodia

Shri Balkavi Bairagi

Shrimati Jamana Devi Barupal

Shri Nilotpal Basu

Prof Ram Deo Bhandary

Shri Hansraj Bhardwaj

Shri Karnendu Bhattacharjee

Shri Manoj Bhattacharya

Sardar Balwinder Singh Bhundar

Shri S.R. Bommai

Shri Drupad Borgohain

Shrimati Chandresh Kumari

Shri T.N. Chaturvedi

Shri S.B. Chavan

Shri Khagen Das

Dr. M.N. Das

Dr. (Ms.) P. Selvie Das

Dr. Biplab Dasgupta

Shri Anantray Devshanker Dave

Shri Sukh Dev Singh Dhindsa

Shrimati Saroj Dubey

Shri V.P. Duraisamy

Dr. Faguni Ram

Shri Eduardo Faleiro

Shri Oscar Fernandes

Shri Sangh Priya Gautam

Shri R. P. Goenka

Shri H.K. Javare Gowda

Shrt Vedprakash P. Goyal

Shri Hiphei

Shri C.M. Ibrahim

Shri Arun Jaitley

Shri M.A. Kadar

Shri Kanshi Ram

Dr. Karan Singh

Shri Swaraj Kaushal

Shri Rama Shanker Kaushik

Shri Suresh A. Keshwani

Shri Aimaduddin Ahmad Khan (Durru)

Shri K.M. Khan

Shri K. Rahman Khan

Shri Ramachandra Khuntia

Dr. A.R. Kidwai

Shri Ram Nath Kovind

Shri Lachhman Singh

Prof. A. Lakshmisagar

Shri Pramod Mahajan

Shri Mahendra Prasad

Shri Bhagatram Manhar

Shri O.S. Manian

Dr. Manmohan Singh

Shri R. Margabandu

Shri Md. Salim

Shri Moolchand Meena

Shri Ranganath Misra

Shri Dipankar Mukherjee

Shri Pranab Mukherjee

Shri K.B. Krishna Murthy

Shri M. Rajasekara Murthy

Dr. Y. Radhakrishna Murty

Shrimati Jayaprada Nahata

Shri M. Venkaiah Naidu

Shri S.Niraikulathan

Shri Sanjay Nirupam

Shri Onward L. Nongtdu

Shri Suresh Pachouri

Shrimati Chandra Kala Pandey

Shri Raju Parmar

Dr. A. K. Patel

Shri S. Ramachandran Pillai

Shri C.O. Poulose

Shri Satish Pradhan

Shri Ravi Shankar Prasad

Shri Balbir K. Punj

Shri Abdul Gaiyur Qureshi

Shri V.V. Raghavan

Shrimati Kum Kum Rai

Shri Lajpat Rai

Shrimati Bimba Raikar

Shri O. Rajagopal

Dr. Alladi P. Rajkumar

Shri C. Ramachandraiah

Shri Cho S. Ramaswamy

Shri K. Kalavenkata Rao

Shri K. Rama Mohana Rao

Mirza Abdul Rashid

Prof. (Shrimati) Bharati Ray

Miss Mabel Rebello

Shri Nabam Rebia

Shri Solipeta Ramachandra Reddy

Shri Abani Roy

Shri Ramachandraiah Rumandla

Shri K.M. Saifullah

Shri N.K.P. Salve

Shri Manmohan Samal

Prof. M. Sankaralingam

Shrimati Basanti Sarma

Shri Bratin Sengupta

Shrimati Savita Sharda

Shri Sharief-Ud-Din Shariq

Dr. Mahesh Chandra Sharma

Shri Arun Shourie

Shri Rajeev Shukla

Shri Arjun Singh

Shri Birabhadra Singh

Shri Devi Prasad Singh

Shri Jaswant Singh

Shri Raj Mohinder Singh

Shri Rajiv Ranjan Singh

Shri W. Angou Singh

Shri B.P. Singhal

Shri Rama Muni Reddy Sirigireddy

Shri P.N. Siva

Shri S. Sivasubramanian

Shri Gopalsinh G. Solanki

Shrimati Ambika Soni

Shri P. Soundararajan

Shri Ka. Ra. Subbian

Shri N. Thalavai Sundaram

Shri Rajnath Singh 'Surya'

Shrimati Sushma Swaraj

Shri C.P. Thirunavukkarasu

Miss Frida Topno

Shri Suryabhan Patil Vahadane

Shrimati Vanga Geetha

Prof. R. B. S. Varma

Shri A. Vijaya Raghavan

Shri S. Viduthalai Virumbi

Shri Ranjan Prasad Yadav

Shri Vijay Singh Yadav

Shri Khan Ghufran Zahidi

Noes - Nil

The motion was carried by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than two thirds of the Members present and voting.

The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now, the question is:

"That the Title stand part of the Bill."

The House divided

THE DEPUTY CHAIRMAN: Ayes - 140

Noes - Nil

Ayes - 140

Shri Parmeshwar Kumar Agarwalla

Shri S. Agniraj

Shri S.S. Ahluwalia

Shri Akhilesh Das

Shri Anil Kumar

Shri B.P. Apte

Shri Gandhi Azad

Shri Gulam Nabi Azad

Shri Bachani Lekhraj

Shri Santosh Bagrodia

Shri Balkavi Bairagi

Shrimati Jamana Devi Barupal

Shri Nilotpal Basu

Prof Ram Deo Bhandary

Shri Hansraj Bhardwaj

Shri Karnendu Bhattacharjee

Shri Manoj Bhattacharya

Sardar Balwinder Singh Bhundar

Shri S.R. Bommai

Shri Drupad Borgohain

Shrimati Chandresh Kumari

Shri T.N. Chaturvedi

Shri S.B. Chavan

Shri Khagen Das

Dr. M.N. Das

Dr. (Ms.) P. Selvie Das

Dr. Biplab Dasgupta

Shri Anantray Devshanker Dave

Shri Sukh Dev Singh Dhindsa

Shrimati Saroj Dubey

Shri V.P. Duraisamy

Dr. Faguni Ram

Shri Eduardo Faleiro

Shri Oscar Fernandes

Shri Sangh Priya Gautam

Shri R. P. Goenka

Shri H.K. Javare Gowda

Shri Vedprakash P. Goyal

Shri Hiphei

Shri C.M. Ibrahim

Shri Arun Jaitley

Shri M.A. Kadar

Shri Kanshi Ram

Dr. Karan Singh

Shri Swaraj Kaushal

Shri Rama Shanker Kaushik

Shri Suresh A. Keshwani

Shri Aimaduddin Ahmad Khan (Durru)

Shri K.M. Khan

Shri K. Rahman Khan

Shri Ramachandra Khuntia

Dr. A.R. Kidwai

Shri Ram Nath Kovind

Shri Lachhman Singh

Prof. A. Lakshmisagar

Shri Pramod Mahajan

Shri Mahendra Prasad

Shri Bhagatram Manhar

Shri O.S. Manian

Dr. Manmohan Singh

Shri R. Margabandu

Shri Md. Salim

Shri Moolchand Meena

Shri Ranganath Misra

Shri Dipankar Mukherjee

Shri Pranab Mukherjee

Shri K.B. Krishna Murthy

Shri M. Rajasekara Murthy

Dr. Y. Radhakrishna Murty

Shrimati Jayaprada Nahata

Shri M. Venkaiah Naidu

Shri S.Niraikulathan

Shri Sanjay Nirupam

Shri Onward L. Nongtdu

Shri Suresh Pachouri

Shrimati Chandra Kala Pandey

Shri Raju Parmar

Dr. A. K. Patel

Shri S. Ramachandran Pillai

Shri C.O. Poulose

Shri Satish Pradhan

Shri Ravi Shankar Prasad

Shri Balbir K. Punj

Shri Abdul Gaiyur Qureshi

Shri V.V. Raghavan

Shrimati Kum Kum Rai

Shri Lajpat Rai

Shrimati Bimba Raikar

Shri O. Rajagopal

Dr. Alladi P. Rajkumar

Shri C. Ramachandraiah

Shri Cho S. Ramaswamy

Shri K. Kalavenkata Rao

Shri K. Rama Mohana Rao

Mirza Abdul Rashid

Prof. (Shrimati) Bharati Ray

Miss Mabel Rebello

Shri Nabam Rebia

Shri Solipeta Ramachandra Reddy

Shri Abani Roy

Shri Ramachandraiah Rumandla

Shri K.M. Saifullah

Shri N.K.P. Salve

Shri Manmohan Samal

Prof. M. Sankaralingam

Shrimati Basanti Sarma

Shri Bratin Sengupta

Shrimati Savita Sharda

Shri Sharief-Ud-Din Shariq

Dr. Mahesh Chandra Sharma

Shri Arun Shourie

Shri Rajeev Shukla

Shri Arjun Singh

Shri Birabhadra Singh

Shri Devi Prasad Singh

Shri Jaswant Singh

Shri Raj Mohinder Singh

Shri Rajiv Ranjan Singh

Shri W. Angou Singh

Shri B.P. Singhal

Shri Rama Muni Reddy Sirigireddy

Shri P.N. Siva

Shri S. Sivasubramanian

Shri Gopalsinh G. Solanki

Shrimati Ambika Soni

Shri P. Soundararajan

Shri Ka. Ra. Subbian

Shri N. Thalavai Sundaram

Shri Rajnath Singh 'Surya'

Shrimati Sushma Swaraj

Shri C.P. Thirunavukkarasu

Miss Frida Topno

Shri Suryabhan Patil Vahadane

Shrimati Vanga Geetha

Prof. R. B. S. Varma

Shri A. Vijaya Raghavan

Shri S. Viduthalai Virumbi

Shri Ranjan Prasad Yadav

Shri Vijay Singh Yadav

Shri Khan Ghufran Zahidi

Noes - Nil

The motion was carried by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than two thirds of the Members present and voting.

The Title was added to the Bill.

SHRIMATI VASUNDHARA RAJE: Madam, I move:

"That the Bill, as amended, be passed."

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now, the question is:

"That the Bill, as amended, be passed."

The House divided

THE DEPUTY CHAIRMAN: Ayes - 140

Noes - Nil

Ayes -140

Shri Parmeshwar Kumar Agarwalla

Shri S. Agniraj

Shri S.S. Ahluwalia

Shri Akhilesh Das

Shri Anil Kumar

Shri B.P. Apte

Shri Gandhi Azad

Shri Gulam Nabi Azad

Shri Bachani Lekhraj

Shri Santosh Bagrodia

Shri Balkavi Bairagi

Shrimati Jamana Devi Barupal

Shri Nilotpal Basu

Prof Ram Deo Bhandary

Shri Hansraj Bhardwaj

Shri Karnendu Bhattacharjee

Shri Manoj Bhattacharya

Sardar Balwinder Singh Bhundar

4522RS F—48-A

Shri S.R. Bommai

Shri Drupad Borgohain

Shrimati Chandresh Kumari

Shri T.N. Chaturvedi

Shri S.B. Chavan

Shri Khagen Das

Dr. M.N. Das

Dr. (Ms.) P. Selvie Das

Dr. Biplab Dasgupta

Shri Anantray Devshanker Dave

Shri Sukh Dev Singh Dhindsa

Shrimati Saroj Dubey

Shri V.P. Duraisamy

Dr. Faguni Ram

Shri Eduardo Faleiro

Shri Oscar Fernandes

Shri Sangh Priya Gautam

Shri R. P. Goenka

Shri H.K. Javare Gowda

Shri Vedprakash P.Goyal

Shri Hiphei

Shri C.M. Ibrahim

Shri Arun Jaitley

Shri M.A. Kadar

Shri Kanshi Ram

Dr. Karan Singh

Shri Swaraj Kaushal

Shri Rama Shanker Kaushik

Shri Suresh A. Keshwani

Shri Aimaduddin Ahmad Khan (Durru)

Shri K.M. Khan

Shri K. Rahman Khan

Shri Ramachandra Khuntia

Dr. A.R. Kidwai

Shri Ram Nath Kovind

Shri Lachhman Singh

Prof. A. Lakshmisagar

Shri Pramod Mahajan

Shri Mahendra Prasad

Shri Bhagatram Manhar

Shri O.S. Manian

Dr. Manmohan Singh

Shri R. Margabandu

Shri Md. Salim

Shri Moolchand Meena

Shri Ranganath Misra

Shri Dipankar Mukherjee

Shri Pranab Mukherjee

Shri K.B. Krishna Murthy

Shri M. Rajasekara Murthy

Dr. Y. Radhakrishna Murty

Shrimati Jayaprada Nahata

Shri M. Venkaiah Naidu

Shri S. Niraikulathan

Shri Sanjay Nirupam

Shri Onward L. Nongtdu

Shri Suresh Pachouri

Shrimati Chandra Kala Pandey

Shri Raju Parmar

Dr. A. K. Patel

Shri S. Ramachandran Pillai

Shri C.O. Poulose

Shri Satish Pradhan

Shri Ravi Shankar Prasad

Shri Balbir K. Punj

Shri Abdul Gaiyur Qureshi

Shri V.V. Raghavan

Shrimati Kum Kum Rai

Shri Lajpat Rai

Shrimati Bimba Raikar

Shri O. Rajagopal

Dr. Alladi P. Rajkumar

Shri C. Ramachandraiah

Shri Cho S. Ramaswamy

Shri K. Kalavenkata Rao

Shri K. Rama Mohana Rao

Mirza Abdul Rashid

Prof. (Shrimati) Bharati Ray

Miss Mabel Rebello

Shri Nabam Rebia

Shri Solipeta Ramachandra Reddy

Shri Abani Roy

Shri Ramachandraiah Rumandla

Shri K.M. Saifullah

Shri N.K.P. Salve

Shri Manmohan Samal

Prof. M. Sankaralingam

Shrimati Basanti Sarma

Shri Bratin Sengupta

Shrimati Savita Sharda

Shri Sharief-Ud-Din Shariq

Dr. Mahesh Chandra Sharma

Shri Arun Shourie

Shri Rajeev Shukla

Shri Arjun Singh

Shri Birabhadra Singh

Shri Devi Prasad Singh

Shri Jaswant Singh

Shri Raj Mohinder Singh

Shri Rajiv Ranjan Singh

Shri W.Angou Singh

Shri B.P. Singhal

Shri Rama Muni Reddy Sirigireddy

Shri P.N. Siva

Shri S. Sivasubramanian

Shri Gopalsinh G. Solanki

Shrimati Ambika Soni

Shri P. Soundararajan

Shri Ka. Ra. Subbian

Shri N. Thalavai Sundaram

Shri Rajnath Singh 'Surya'

Shrimati Sushma Swaraj

Shri C.P. Thirunavukkarasu

Miss Frida Topno

Shri Suryabhan Patil Vahadane

Shrimati Vanga Geetha

Prof. R. B. S. Varma

Shri A. Vijaya Raghavan

Shri S. Viduthalai Virumbi

Snri Ranjan Prasad Yadav

Shri Vijay Singh Yadav

Shri Khan Ghufran Zahidi

Noes - Nil

The motion was carried by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than two-thirds of the Members present and voting.

THE CONSTITUTION (EIGHTY-SIXTH AMENDMENT) BILL, 1999

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (SHRI A. RAJA) : Madam, I move:

"That the Bill further to amend the Constitution of India, be taken into consideration."